CNews मिटी चीफ

मिटी चीफ

वर्ष-15, अंक-317
पृष्ठ-8 मूल्य 2 रूपया

मीठा बोलने में एक कौड़ी भी खर्च नहीं होती, इसलिए सदा प्रेमयुक्त, मधुर व सत्य वचन बोलें।

CITYCHIEFSENDMENEWS@GMAIL.COM

इंदौर, शुक्रवार 21 फरवरी 2025

सम्पूर्ण भारत मे चर्चित हिन्दी अखबार

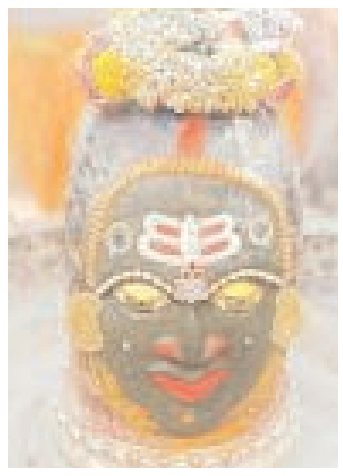

छावा बनी 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म, 270 करोड़ की कमाई

मुंबई। विकी कौशल की छावा बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है। विकी कौशल और अक्षय खन्ना, दोनों ने अपने किरदार को बखूबी निभाया है। फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर कई वीडियो भी सामने आ रहे हैं जिसमें लोग फिल्म देखकर भावुक होते नजर आ रहे हैं। विकी कौशल की यह फिल्म साल 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। बुधवार तक की कमाई की बात करें तो विकी कौशल की फिल्म ने दुनियाभर में कुल 270 करोड़ की कमाई कर ली है। वहीं, माना जा रहा है कि गुरुवार को फिल्म का 300 करोड़ का आंकड़ा पार करने का अनुमान जाताया जा रहा है। पहले 6 दिन में विकी कौशल की फिल्म छावा ने भारत में 197.75 करोड़ की कमाई कर ली थी। बुधवार को फिल्म की कमाई में बड़ा उछाल देखने को मिला। बुधवार को भारत में छावा ने कुल 32 करोड़ की कमाई की। बुधवार की कमाई के साथ ही विकी कौशल की छावा साल 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई है। इससे पहले अक्षय कुमार की स्काई फोर्स सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। अक्षय कुमार की स्काई फोर्स ने 168 करोड़ की कमाई की थी।

भूखे रहकर देशभर के रेलवे ड्राइवर चला रहे ट्रेनें

लोको पायलटों की 'गांधीगीरी'

नई दिल्ली। देश में कानूनन एक दिन में 8 घंटे की ड्यूटी करने का प्रावधान है। लेकिन रेलवे के लोको पायलटों का कहना है कि वे 11 घंटे से 16 घंटे तक लगातार ड्यूटी करते हैं। इस वजह से हादसे भी होते रहते हैं। लेकिन सरकार की तरफ से उनके लिए समधान नहीं निकला है। इसलिए, उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बताए रास्ते पर चलने का फैसला किया। जी हां, देशभर के लोको पायलटों ने गुरुवार सुबह आठ बजे से 36 घंटे तक का उपवास शुरू कर दिया है। इस अवधि के दौरान जिन लोको पायलट्स की ड्यूटी पड़ेगी वे काम करेंगे, लेकिन भोजन नहीं करेंगे। वे भूखे पेट काम करेंगे और सरकार के समक्ष अपना विरोध जताएंगे। लोको पायलटों या रेलवे के ड्राइवरों के प्रतिनिधि संगठन ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन ने इस उपवास का आह्वान किया है। यह उपवास गुरुवार सुबह आठ बजे से शुरू हो गया है और शुक्रवार रात आठ बजे तक चलेगा। एसोसिशन के अध्यक्ष आरआर भगत ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ट्रेनों के लोको पायलट गुरुवार सुबह आठ बजे से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। जो लोग ड्यूटी में हैं, वेभूखे रहकर काम कर रहे हैं। जो रेस्ट में हैं, वेडीआरएम ऑफिस के सामने भूखे रहकर धरना दे रहे हैं। भगत का कहना है कि लोको पायलटों को भारी दबाव के बीच काम करना पड़ रहा है। मालगाड़ी के पायलटों की बात करें तो उन्हें औसतन 11 घंटे तक काम करना पड़ता है। कभी-कभी तो वे 13 घंटे, 16 घंटे तक ड्यूटी करते हैं। इस वजह से दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं।

यह है लोको पायलटों की मांग
लोको पायलट चाहते हैं कि मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों में छह घंटे और मालगाड़ी में आठ घंटे की ड्यूटी का रोस्टर हो। उनका कहना है कि 19वीं सदी में, जब औद्योगिक क्रांति आई थी, आठ घंटे काम, आठ घंटे विश्राम और आठ घंटे परिवार के लिए पूरी दुनिया की बुनियादी श्रम मांगें थीं। यह बिल्कुल भयावह है कि आजादी के 77 साल बाद भी सरकार के अधीन केंद्रीय सरकारी संस्थान में 8 घंटे के काम के लिए संघर्ष कर रहे हैं। संगठन के अनुसार, पूरे देश के 367 डिपो और 36 रेल मंडलों के लोको पायलट एवं सहायक लोको पायलट 21 दिनों का नोटिस दे चुके हैं, जिसके बाद वे भूख हड़ताल और अन्य विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। एसोसिएशन का कहना है कि 1 जनवरी 2024 से लागू किए गए डिवाल्विंग एलाउंस में 25 प्रतिशत की कटौती से लोको पायलटों को भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है।

रोगी बन जाते हैं ट्रेन ड्राइवर
लोको पायलटों का कहना है कि इस बारे में कई स्टडीज हो चुकी है। लगातार 85 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि सुनने से सुनने की शक्ति पर गंभीर असर पड़ सकता है, लेकिन उनमें से हर किसी को 95 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि में 10 और 15 घंटे काम करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। जब वह ट्रेन लेकर कई स्टेशनों और सिगनलों से 100 और 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गुजरते हैं तो लोको में भीषण कंपन होता है। इससे शरीर में जो दर्द होता है उसकी तुलना किसी कार्यालय में आठ घंटे काम करने वाले व्यक्ति से कैसे की जा सकती है। इसी वजह से अधिकतर लोको पायलट हाई ब्लड प्रेशर और शुगर के मरीज बन जाते हैं।

अमेरिका के राष्ट:पति डोनाल्ड ट्रंप बोले- ज्यादा दूर नहीं तीसरा विश्व युद्ध, लेकिन इसे रोकेंगे

न्यूयॉर्क। अमेरिका के राष्ट:पति डोनाल्ड ट्रंप शपथ लेने के बाद से ही लगातार मध्य-पूर्व और यूरोप में चल रहे युद्ध को खत्म करने को लेकर बयान दे रहे हैं। अब इन संघर्षों के बारे में बात करते हुए ट्रंप ने तीसरे विश्व युद्ध को लेकर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि जिस तरह के हालात चल रहे हैं उससे लगता है कि तीसरा विश्व युद्ध ज्यादा दूर नहीं है। लेकिन मेरा अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर होना इसे रोकेगा। मेरे पास विश्व युद्ध को रोकने का प्लान है। सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक मियामी में एक सभा को संबोधित करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि हम दुनियाभर में चल रहे युद्धों को समाप्त करने और दुनिया में शांति बहाल करने में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हम नहीं चाहते कि अब और ज्यादा लोग युद्ध की वजह से मरें। उन्होंने कहा कि अगर हम मध्य-पूर्व और यूक्रेन में हुई मौतों को देखें को आप समझ सकते हैं कि आप तीसरे विश्व युद्ध से ज्यादा दूर नहीं है। ट्रंप ने अपने पूर्ववर्ती बाइडन प्रशासन को निशाने पर लेते हुए कहा कि अगर में एक साल और बाइडन का राज होता तो निश्चित तौर पर दुनिया तीसरे विश्व युद्ध को देख रही होती। लेकिन अब जबकि मैं अमेरिका का राष्ट्रपति हूं तो अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला।

मध्यप्रदेश में आज से फिर गिरेगा तापमान, भोपाल-ग्वालियर में छाएंगे बादल

मध्यप्रदेश में मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है। शुक्रवार से दिन और रात के तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि अगले कुछ दिनों में तापमान 2 से 3 डिग्री तक कम हो सकता है। भोपाल और ग्वालियर में बादल छाने की संभावना है, जबकि इंदौर और उज्जैन में आसमान साफ रहेगा। क्यों बदल रहा है मौसम? फरवरी के आखिरी दिनों में मौसम का यही रुख बना रहेगा। वर्तमान में दक्षिण पाकिस्तान और राजस्थान के ऊपर एक साइक्लोनिक सकुर्लेशन सक्रिय है।

चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया का धमाकेदार आगाज, बांग्लादेश को 6 विकेट से हराया

गिल ने जीता दिल

मोहम्मद शमी ने 5, हर्षित राणा ने 3 और अक्षर पटेल ने 2 विकेट झटके

नई दिल्ली। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आगाज टीम इंडिया ने जीत के साथ किया है। दुबई में खेले गए अपने पहले मैच में बांग्लादेश को टीम इंडिया ने 6 विकेट से हराकर टूर्नामेंट में तूफानी शुरुआत की। इस जीत के साथ भारतीय टीम ग्रुप ए में टॉप 2 में पहुंचने में भी सफल हुई है। इस मुकाबले में भारतीय टीम के लिए गेंद से मोहम्मद शमी और बल्ले से शुभमन गिल हीरो रहे। शमी ने पंजा खोला, जबकि गिल ने दमदार शतक जड़ा। रोहित शर्मा ने भी तूफानी पारी खेलकर टीम को दमदार शुरुआत दिलाई थी। शुभमन गिल नाबाद शतक जड़ने के कारण प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। इस मुकाबले की बात करें तो बांग्लादेश की टीम के कप्तान नजमुल हुसैन शांतो ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी थी। हालांकि, टीम को अच्छी शुरुआत नहीं मिली। 35 रन पर 5 विकेट गिर चुके थे। एक समय लग रहा था कि बांग्लादेश की टीम के लिए 125 रन भी बनाना मुश्किल है, लेकिन जाकिर अली और तौहीद हृदय ने 154 रनों की साझेदारी की और मैच में बांग्लादेश की वापसी कराई। जाकिर अली 68 रन बनाकर आउट हो गए थे, लेकिन तौहीद हृदय ने शतक जड़कर टीम को अच्छी स्थिति में पहुंचाया था।

बांग्लादेश की टीम ने 49.4 ओवर में सभी विकेट खोकर 228 रन बनाए थे। भारत की ओर से पांच विकेट मोहम्मद शमी ने चटकाए, जबकि तीन विकेट हर्षित राणा को मिले और दो सफलताएं एक ही ओवर में अक्षर पटेल को मिलीं। वहीं, भारतीय टीम को 229 रनों के जवाब में कप्तान रोहित शर्मा ने शुभमन गिल के साथ मिलकर तूफानी शुरुआत दिलाई।

शुभमन गिल ने 125 गेंदों में बनाया शतक रोहित शर्मा 36 गेंदों में 41 रन बनाकर आउट हुए थे। उस समय तक स्कोर 70 के करीब था। इसके बाद शुभमन गिल और विराट कोहली के बीच एक छोटी सी साझेदारी हुई। इस दौरान विराट कोहली 22 रन बनाकर चलते बने। वहीं, एक छोर पर शुभमन गिल डटे रहे। उन्होंने श्रेयस अय्यर (15) और अक्षर पटेल (8) के साथ कुछ रन जोड़े। हालांकि, केएल राहुल के साथ उनकी साझेदारी ने मैच बनाया। शुभमन गिल ने 125 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। केएल राहुल ने उनका आखिर तक साथ दिया। शतक के लिए उन्होंने कुछ गेंदें भी डिफेंड कीं। हालांकि, केएल राहुल का कैच जाकिर अली ने छोड़ दिया था, जो बांग्लादेश को भारी पड़ गया। भारत ने 46.3 ओवर में 4 विकेट खोकर इस लक्ष्य को हासिल कर लिया और ग्रुप ए में दूसरा स्थान हासिल कर लिया।

शमी ने बनाया सबसे कम गेंदों में 200 विकेट लेने का रिकॉर्ड भारत के लिए मोहम्मद शमी ने 5 विकेट लिए। हर्षित राणा ने 3 और अक्षर पटेल ने 2 विकेट झटके। बांग्लादेश से 4 बैटर्स खाता भी नहीं खोल सके। भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने बांग्लादेश के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के मैच में दमदार गेंदबाजी की। इस मुकाबले में जैसे ही उनको तीसरी सफलता मिली, वैसे ही एक वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने अपने नाम कर लिया। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे कम गेंदों में 200 विकेट लेने का कीर्तिमान उन्होंने अपने नाम कर लिया है। इस मामले में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज गेंदबाज मिचेल स्टार्क को पीछे छोड़ दिया है। हालांकि, मैचों के हिसाब से देखें तो मिचेल स्टार्क भारतीय पेसर शमी से आगे हैं। शमी भारत के पहले ऐसे गेंदबाज हैं, जिन्होंने सबसे कम मैचों में 200 विकेट वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में निकाले हैं।मोहम्मद शमी ने जैसे ही बांग्लादेश के खिलाफ 43वें ओवर की चौथी और अपने कोटे के 8वें ओवर में अपनी तीसरी सफलता मैच की हासिल की तो इसी के साथ उन्होंने विकेट की डबल सेंचुरी वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में पूरी कर ली। वे भारत के लिए सबसे कम मैचों में ऐसा करने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं, जबकि दुनिया के दूसरे गेंदबाज वे सबसे कम मैचों में 200 ओडीआई विकेट चटकाने वाले बन गए हैं।

सीएम मोहन यादव ने मेधावी छात्रों को दिया तोहफा

89 हजार छात्रों के खातों में ट्रांसफर किए 224 करोड़ रुपए

मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के मेधावी छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए एक और सराहनीय कदम उठाया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल स्थित प्रशासन अकादमी में आयोजित कार्यक्रम के दौरान एमपी बोर्ड 2023-24 की 12वीं कक्षा में 75% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले 89,710 छात्रों के खातों में 224 करोड़ रुपये की राशि ट्रांसफर की। कार्यक्रम में नरसिंहपुर के निजी मल्टीपरपज स्कूल की गीता लोधी, 98% अंक पाने वाली स्टूडेंट को पहला लैपटॉप दिया गया। कार्यक्रम में नरसिंहपुर के निजी मल्टीपरपज स्कूल की गीता लोधी, 98% अंक पाने वाली स्टूडेंट को पहला लैपटॉप दिया गया। इस अवसर पर स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

प्रत्येक छात्र को 25 हजार रुपए मिले राज्य सरकार की इस योजना के तहत, हर मेधावी छात्र को 25,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जा रही है, ताकि वे अपने लैपटॉप खरीदने का सपना पूरा कर सकें। यह योजना उन छात्रों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद साबित होगी जो वर्तमान में विभिन्न कॉलेजों में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।

कार्यक्रम में ये नेता रहे मौजूद इस महत्वपूर्ण अवसर पर भोपाल जिले के प्रभारी मंत्री एवं सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री चैतन्य काश्यप, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कृष्णा गौर और सांसद आलोक शर्मा भी उपस्थित रहे।

पहले दी थी ई-स्कूटी, अब लैपटॉप योजना का लाभ बता दें कि इससे पहले 5 फरवरी को मध्य प्रदेश सरकार ने 12वीं बोर्ड परीक्षा में टॉप करने वाले 7,900 छात्रों को ई-स्कूटी प्रदान की थी। तब मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा था कि राज्य सरकार मेधावी छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उसी समय उन्होंने लैपटॉप योजना की भी घोषणा की थी, जिसे अब सफलतापूर्वक लागू कर दिया गया है।

मेधावी छात्र योजना मध्य प्रदेश सरकार की यह पहल छात्रों को न केवल डिजिटल शिक्षा से जोड़ने में मदद करेगी, बल्कि उन्हें आधुनिक तकनीक के साथ आगे बढ़ने का अवसर भी देगी। सरकार द्वारा मेधावी छात्र योजना के तहत दी जाने वाली यह राशि उनके करियर को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में सहायक होगी।

इंदौर में अब अप्रैल में बढ़ेगी संपत्ति की गाइड लाइन, डेढ़ सौ नए इलाके जुड़ेंगे

इंदौर। एक अप्रैल से इंदौर के कुछ इलाकों की प्रॉपर्टी गाइडलाइन बढ़ाने की तैयारी कर ली गई है। गाइडलाइन बढ़ाने का प्रस्ताव अक्टूबर माह में भी भेजा गया था, लेकिन प्रस्ताव को हरी झंडी नहीं मिली। अब पंजीयन विभाग ने सालभर में हुए सौदों का आकलन करते हुए उन इलाकों को चुना है, जहां गाइडलाइन तीन से लेकर दस प्रतिशत तक बढ़ेगी। इसके अलावा डेढ़ सौ से ज्यादा नए इलाके भी कलेक्टर गाइडलाइन के दायरे में आएंगे। इनमें ज्यादातर इलाके बाइपास और शहरी सीमा से सटे हुए हैं, जो नगर निगम सीमा में शामिल हो चुके हैं। नई कॉलोनियों और टाउनशिपों में दो साल पहले नगर निगम ने भी संपत्तिकर बढ़ाया था।मूल्याकंन समिति की बैठक में डेढ़ हजार से ज्यादा लोकेशन की गाइडलाइन बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी पहले ही दे चुकी है। अब उस प्रस्ताव को समिति सरकार के पास फिर से भेजेगी। इन इलाकों में दस से लेकर तीस प्रतिशत तक प्रॉपर्टी की गाइड लाइन में इजाफा होगा। यह बढ़ोतरी उन क्षेत्रों में होगी, जहां सालभर में सबसे ज्यादा रजिस्ट्री हुई और वर्तमान कलेक्टर गाइडलाइन से ज्यादा कीमत पर सौदे हुए।

गाइड लाइन से दो से तीन गुना कीमतों पर हुए सौदे बीते साल इंदौर में तय गाइडलाइन से दो से तीन गुना कीमतों पर जमीनों के सौदे हुए है। सालभर में हुई खरीदी बिक्री के सौदों का आंकलन करते हुए उन क्षेत्रों में ही गाइडलाइन बढाने पर अफसरों ने फोकस किया है। इसके अलावा इंदौर शहर से जुड़े ग्रामीण क्षेत्रों में नई कॉलोनियां विकसित हो रही हैं। उनके पंजीयन के लिए भी पंजीयन कार्यालय के पास प्रस्ताव आए हैं। अभी 4000 से ज्यादा लोकेशन पर पंजीयन हो रहे हैं। नई गाइडलाइन आने के बाद 5500 से ज्यादा लोकेशन के लिए पंजीयन कार्यालय में दस्तावेज के पंजीयन हो सकेंगे।

सांवेर रोड और खंडवा रोड पर ज्यादा सौदे इंदौर में बीते साल सांवेर-उज्जैन रोड, खंडवा रोड, सुपर कॉरिडोर, पालाखेड़ी, एरोड्रम रोड की तरफ ज्यादा जमीनों के सौदे हुए हैं। इन क्षेत्रों में नई टाउनशिपों का निर्माण भी हुआ है। इंदौर-खंडवा और इंदौर उज्जैन मार्ग को छह लेन किया जा रहा है। इस कारण यहां जमीनों के भाव में तेजी नजर आ रही है। इन इलाकों में 10 प्रतिशत तक गाइडलाइन बढ़ सकती है। दो माह में पंजीयन विभाग में सबसे ज्यादा रजिस्ट्रियां होती हैं। एक अप्रैल को गाइड लाइन बढ़ने के संकेत के कारण अभी पंजीयन कराने में लोग ज्यादा रुचि ले रहे हैं।

गंगवाल बस स्टैंड पर गंदगी देख भड़के निगम आयुक्त, लगाया जुर्माना

सिटी चीफ इंदौर।

इंदौर। नगर निगम आयुक्त शिवम वर्मा गुरुवार को अचानक गंगवाल बस स्टैंड पहुंचे। उन्होंने परिसर का निरीक्षण करते हुए, सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान उन्हें कई खामियां नजर आईं, जिस पर वे नाराज हो गए। आयुक्त ने कमियों को लेकर अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। आयुक्त ने गंगवाल बस स्टैंड परिसर की सफाई व्यवस्था की समीक्षा की, जिसमें कई खामियां सामने आईं। उन्होंने पाया कि, वहां नियमित रूप से पर्याप्त सफाई नहीं हो रही थी। जांच में पता चला कि संबंधित सुपरवाइजर रोजाना दोपहर 12 बजे देवास से इंदौर आता है। इस लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए आयुक्त ने उसका 10 दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए।

इसके बाद उन्होंने बस स्टैंड के रैन बसेरा और वाटर सुलभ कॉम्प्लेक्स का भी निरीक्षण किया। जांच के दौरान टिकट काउंटर के पास वाहनों की अव्यवस्थित पार्किंग पाई गई, जिस पर संबंधित व्यक्ति पर 5,000 रुपए का स्पॉट फाइन लगाया गया।

रैन बसेरा में वाटर कूलर खराब मिले

इसके अलावा, रैन बसेरा में वाटर कूलर खराब मिलने और सफाई व्यवस्था में कमी पाए जाने पर संलग्न एजेंसी पर 5,000 रुपए की पेनल्टी लगाने के निर्देश जारी किए गए। आयुक्त ने रैन बसेरा में आवश्यक सफाई व्यवस्था और रखरखाव में सुधार के लिए भी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। नगर निगम आयुक्त शिवम वर्मा ने कहा कि, शहर की स्वच्छता व्यवस्था में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि, गंगवाल बस स्टैंड पर प्रतिदिन बड़ी संख्या में यात्रियों की आवाजाही होती है और यहां से लगभग 180 बसें संचालित होती हैं। यात्रियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

बस स्टैंड के बाहरी हिस्से की पेंटिंग का कार्य पूरा

आयुक्त ने बताया कि, बस स्टैंड के बाहरी हिस्से की पेंटिंग का कार्य पूरा हो चुका है, जबकि शेष कार्य भी शीघ्र पूरा कर लिया जाएगा। संबंधित अधिकारियों एवं एजेंसियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। निरीक्षण के दौरान अधीक्षण यंत्री डी.आर. लोधी, मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अखिलेश उपाध्याय सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने किया जमकर प्रदर्शन, दी चेतावनी

सिटी चीफ इंदौर।

इंदौर। कोर्ट से लेकर केबिनेट के फैसलों को नजरअंदाज करने की वजह से मेडिकल कॉलेज, टीचर डॉक्टर्स और प्रोफेसर्स ने गुरुवार से काली पट्टी बांधकर शासन के खिलाफ विरोध जताना शुरू कर दिया है। मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन का कहना है कि हम 24 फरवरी तक लोकतांत्रिक तरीके से विरोध जताते रहेंगे, मगर इसके बावजूद शासन ने कोर्ट के आदेश और केबिनेट द्वारा मंजूर फैसलों पर अमल नहीं किया तो अपने अधिकारों के लिए आर-पार की लड़ाई लड़ने के लिए मजबूरी में उग्र आंदोलन चलाना पड़ेगा। गुरुवार से मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन एमजीएम के नेतृत्व में जिला अस्पताल, ईएसआई अस्पताल, मेडिकल कॉलेज में काली पट्टी लगाकर विरोध जताना शुरू कर दिया है। शुक्रवार को लंच टाइम में आधे घंटे 1 से 2 बजे तक अपने कार्यस्थल के बाहर विरोध प्रदर्शन करेंगे। इसके बाद 22 फरवरी को प्रदेश के समस्त चिकित्सक सामूहिक उपवास रखेंगे, वहीं लंच टाइम में मास्क पहनकर कार्य स्थल के बाहर विरोध प्रदर्शन करेंगे। इसके बाद 24 फरवरी इंदौर सहित प्रदेश के सारे चिकित्सक सामूहिक उपवास करते हुए चिन्हित अस्पतालों में जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ के विरोध में अमानक दवाइयों की सांकेतिक होली जलाएंगे, वहीं 25 फरवरी से इंदौर से लेकर सारे राज्य में प्रदेशव्यापी उग्र आंदोलन शुरू किया जाएगा।

दो सप्ताह में मुद्दे सुलझाने का आदेश दिया था

उच्च न्यायालय द्वारा 4 दिसंबर 2024 के अपने आदेश में 2 सप्ताह में हाई पॉवर कमिटी का गठन एवं उससे अगले 2 सप्ताह में डॉक्टरों के मुद्दे सुलझाने का आदेश दिया गया था, जो आज दिनांक तक लागू नहीं किया गया। मध्य प्रदेश कैबिनेट से पारित समयमान चयन वेतनमान का अभी तक कई चिकित्सकों एवं चिकित्सा शिक्षकों को लाभ नहीं मिल रहा है। 4 अक्टूबर 2023 में पारित आदेश के अनुसार सातवें वेतनमान का वास्तविक लाभ जनवरी 2016 से दिया जाना था, साथ ही एनपीए की गणना सातवें वेतनमान के अनुरूप होनी चाहिए थी, लेकिन अब तक इस पर कोई अमल नहीं हुआ है। एमपीपीएचसीएल द्वारा सप्लाई की गई कई दवाइयां अमानक पाई गईं, जिनमें कुछ दवाइयां आईसीयू और ऑपरेशन थिएटर में उपयोग होने वाली जीवनरक्षक दवाइयां भी शामिल हैं। यह मामला उजागर होने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। कोलकाता के आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज में हुई दुखद घटना के बाद भी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में कोई पहल नहीं की गई है।

उग्र हो सकता है आंदोलन

तकनीकी विशेषज्ञों के स्थान पर प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति के कारण प्रदेश की स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा व्यवस्था अधर में लटक चुकी है। इस लापरवाही और अनदेखी के खिलाफ डॉक्टर और मेडिकल प्रोफेसर अब आर-पार की लड़ाई के मूड में हैं और अगर सरकार जल्द से जल्द समाधान नहीं निकालती तो उग्र आंदोलन अपरिहार्य होगा।

बिजली काटने गए लाइनमैन और टीम के साथ मारपीट, छत से ईंटें फेंकी

सिटी चीफ इंदौर।

इंदौर। इंदौर के मल्हारगंज इलाके में एमपीईबी के लाइनमैन और स्टाफ के साथ मारपीट की घटना सामने आई है। बताया जाता है कि, एक उपभोक्ता के घर पर बिजली बिल बकाया होने के कारण लाइनमैन अपने साथी के साथ वहां पहुंचा था। इस दौरान उपभोक्ता ने विवाद करते हुए लाइनमैन और उसकी टीम के साथ मारपीट की और उन पर छत से ईंटें फेंकी। मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। मल्हारगंज टीआई वीरेंद्र कुशवाह के मुताबिक, कैलाश पुत्र रामप्रसाद यादव निवासी आदर्श मौलिक नगर की शिकायत पर मनीष पुत्र श्यामराव काले निवासी इंद्रानगर के खिलाफ मारपीट और शासकीय कार्य में बाधा डालने के आरोप में कार्रवाई की गई है। कैलाश ने पुलिस को दी गई शिकायत में बताया कि, वह कालानी नगर पावर हाउस में लाइनमैन के पद पर कार्यरत है। बुधवार दोपहर वह

एमपीईबी कार्यालय से कर्मचारी राजीव, मनोहर, हर्ष और पीयूष के साथ मनीष काले के घर पहुंचे, जहां करीब 35 हजार रुपए से अधिक का बिल बकाया था। बकाया भुगतान न होने के कारण टीम कनेक्शन काटने लगी, जिससे मनीष नाराज हो गया। मनीष ने विद्युत मंडल के कर्मचारियों के साथ अभद्र भाषा में बातचीत की और धमकाने लगा। इसके बाद उसने हाथापाई भी की। जब उसे समझाने की कोशिश की गई, तो वह घर के अंदर चला गया। इस दौरान टीम पोल से कनेक्शन काटने का काम करने लगी, तभी मनीष छत पर आ गया और ईंटें फेंकने लगा। इस हमले में लाइन पर काम कर रहे हर्ष मकवाना घायल हो गए। इसके बाद बिजली कंपनी के अधिकारियों को घटना की सूचना दी गई, जिसके बाद आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया गया।

बावड़ी पर बनी चार दुकानें नगर निगम ने हटाई

सिटी चीफ इंदौर।

इंदौर। इंदौर के राजकुमार ब्रिज के नीचे वल्लभ नगर क्षेत्र में नगर निगम की रिमूवल टीम ने कार्रवाई की। गुरुवार को टीम दलबल के साथ यहां पहुंची। यहां पर बावड़ी पर बनी चार दुकानों को हटाने की कार्रवाई की गई है। बताया जा रहा है कि, बावड़ी पर स्लैब डालकर इस पर अतिक्रमण कर लिया गया था। यहां पर चारों दुकानें बंद पड़ी थी, जिनकी हालत भी जर्जर हो चुकी थी। निगम आयुक्त शिवम वर्मा के निर्देश के बाद टीम ने यहां कार्रवाई की है। गुरुवार को नगर निगम की रिमूवल टीम दो जेसीबी और पुलिस बल के साथ राजकुमार ब्रिज के नीचे वल्लभ नगर क्षेत्र में पहुंची।

यहां पर बनी चार दुकानों को हटाने की कार्रवाई की गई है। अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक, यहां बावड़ी पर स्लैब डालकर अतिक्रमण कर लिया गया था। यहां पर बनी दुकानों की स्थिति भी जर्जर थी। दुकानों की स्थिति को देखते हुए कोई अप्रिय घटना न हो इसके चलते रिमूवल विभाग ने इस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए दुकानों को हटा दिया।

कैदियों ने प्रयागराज संगम से लाए गए जल में लगाई डुबकी

सिटी चीफ इंदौर।

इंदौर। केंद्रीय जेल में एक अनोखा नजारा देखने को मिला है। यहां के कैदियों के लिए महाकुंभ से लाए गए पवित्र संगम जल से स्नान की विशेष व्यवस्था की गई। जेल प्रशासन द्वारा यह आयोजन कैदियों को धर्म, अध्यात्म और सनातन संस्कृति से जोड़ने के उद्देश्य से किया गया इस आयोजन के लिए जेल परिसर में विशेष रूप से बड़े-बड़े कुंड बनाए गए, जिनमें विधिवत पूजा-अर्चना और मंत्रोच्चार के साथ गंगा नदी का पवित्र जल भरा गया। इन कुंडों में गुलाब की पंखुड़ियां भी डाली गईं, जिससे वातावरण पूरी तरह आध्यात्मिक हो गया। इस पवित्र स्नान के दौरान कैदियों ने हर-हर गंगे के जयघोष किए और धार्मिक आस्था से ओत-प्रोत माहौल बना रहा। करीब 2400 से अधिक कैदियों ने इस विशेष स्नान में भाग लिया। कई कैदियों ने उपवास रखकर इसे और भी

विशेष बनाया और अपने जीवन में बदलाव लाने का संकल्प लिया। जेल अधीक्षक अलका सोनकर ने बताया कि कुछ सामाजिक संगठनों और परिचितों की मदद से शाही स्नान के दिन का पवित्र गंगाजल इंदौर लाया गया था। जेल परिसर में अलग-अलग कुंड बनाए गए, जिनमें इस गंगाजल को भरा गया, ताकि अधिक से अधिक कैदी इस आध्यात्मिक अनुभव का लाभ उठा सकें। इंदौर केंद्रीय जेल प्रदेश की पहली ऐसी जेल बन गई है, जहां इस तरह का विशेष आयोजन किया गया। जेल अधीक्षक अलका सोनकर ने बताया कि सरकार का उद्देश्य बंदियों को सुधारकर समाज की मुख्यधारा से जोड़ना है। इस आयोजन से कई कैदियों ने संकल्प लिया कि वे भविष्य में समाज सेवा में अपना जीवन समर्पित करेंगे और सकारात्मक कार्यों से जुड़ेंगे।

महिला ने शादी के बाद पति को दी रेप की जानकारी, पति के साथ पहुंची थाने

सिटी चीफ इंदौर।

इंदौर। इंदौर के खुड़ैल इलाके में एक महिला ने शादी के बाद पति को अपने साथ हुई दरिंदगी की जानकारी दी, जिसके बाद आरोपी से पूछताछ करने पर उसे धमकी मिलने लगी। आखिरकार दंपती ने हिम्मत जुटाकर थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और उसकी तलाश जारी है।

पुलिस के मुताबिक, घटना 15 फरवरी 2020 की है, जब पीड़िता नाबालिग थी। वह अपने परिवार के साथ दूधिया इलाके में मजदूरी करने गई थी और वहां किराये पर रह रही थी। एक दिन बहन से विवाद होने के बाद वह गुस्से में देवगुराड़िया मंदिर चली गई। मंदिर के पीछे जंगल में गई तो पड़ोसी डेपानाथ वहां पहुंचा और उसे जबरन पहाड़ी के पीछे ले जाकर दुष्कर्म किया। डर के कारण पीड़िता ने यह बात किसी को नहीं बताई। बालिग होने के बाद पीड़िता की शादी हो गई।

कुछ समय बाद उसने पति को इस घटना के बारे में बताया। पति ने हिम्मत कर आरोपी से बात की, लेकिन उसने धमकाना शुरू कर दिया। इसके बाद दोनों ने खुड़ैल थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म और धमकी देने की धाराओं में केस दर्ज किया है। जल्द ही उसकी गिरफ्तारी की जाएगी।

रंगपंचमी पर निकलने वाली गेर में शामिल होने के लिए सीएम को न्योता

इंदौर। इंदौर में रंगपंचमी पर निकलने वाली गेर में मोहन सरकार के शामिल होने की संभावना है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव, विधायक गोलू शुक्ला ने मुख्यमंत्री को पूरी कैबिनेट के साथ गेर में शामिल होने का न्योता दिया है। पिछले साल भी मुख्यमंत्री ने गेर में भाग लिया था और रंगों के इस उत्सव में जमकर होली खेली थी। बता दें कि, इंदौर में होलिका दहन के बाद धुलेंडी मनाई जाती है और इसके बाद रंगपंचमी पर गेर निकालने की परंपरा है। इस गेर में लाखों लोग एक साथ होली खेलते हैं। खास बात यह है कि इसे देखने के लिए विदेशों से भी पर्यटक आते हैं। वहीं, इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल कराने के प्रयास भी जारी है। इंदौर में रंगों का सबसे बड़ा त्योहार रंगपंचमी पर बनाया जाता है। गेर एक प्रकार का जुलूस होता है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग एक साथ निकलते हैं। वहीं इंदौर में गेर निकालने की परंपरा होलकर राजवंश के लोगों ने शुरू की थी।

कृषि उपज मंडियों में अव्यवस्थाओं के विरोध में किसानों ने किया प्रदर्शन

सिटी चीफ इंदौर।

इंदौर। इंदौर की तीनों कृषि उपज मंडियों में अव्यवस्थाओं के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। चोइथराम मंडी, लक्ष्मी नगर मंडी और छावनी मंडी में बढ़ती चोरी और अवैध वसूली से किसान, व्यापारी और हम्माल परेशान हैं। संयुक्त किसान मोर्चा का कहना है कि, मंडियों में असामाजिक तत्वों का दबदबा बढ़ता जा रहा है। मारपीट की घटनाएं आम हो गई हैं। लाइसेंसी हम्मालों के अलावा गैर-लाइसेंसी हम्माल भी सक्रिय हैं। ये लोग अक्सर झगड़े करते हैं। इन समस्याओं के कारण मंडियों में व्यापार

प्रभावित हो रहा है। किसान संघर्ष समिति, अखिल भारतीय किसान मजदूर संगठन, किसान मजदूर सभा, भारतीय किसान मजदूर सेना और किसान सभा ने संयुक्त रूप से प्रदर्शन किया। रामस्वरूप मंत्री, बबलू जाधव, शैलेंद्र पटेल, प्रमोद नामदेव, अरुण चौहान, रुद्रपाल यादव और मुन्नालाल कौशल ने प्रदर्शन का नेतृत्व किया। प्रदर्शनकारियों ने एसडीएम गोपाल वर्मा के माध्यम से कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने मंडी सचिव को इंदौर से हटाने की मांग की। उनका कहना है कि, मंडी सचिव और उनके अधीनस्थ अधिकारी अवैध वसूली और मंडी की खराब व्यवस्था के लिए जिम्मेदार हैं। किसानों ने सरकारी योजनाओं में भूमि अधिग्रहण का भी विरोध किया। उनका कहना है कि, एक तरफ उनकी उपजाऊ जमीन छीनी जा रही है, दूसरी तरफ मंडियों में भी उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

प्रदेशभर के 15 हजार से ज्यादा डॉक्टरों का विरोध शुरू, काली पट्टी बांधकर किया काम

सिटी चीफ इंदौर।

भोपाल। राजधानी भोपाल समेत प्रदेश भर के सरकारी मेडिकल कॉलेज और निजी मेडिकल कॉलेज के 15000 से ज्यादा डॉक्टर विरोध करना शुरू कर दिया है पहले दिन कार्यस्थल पर काली पट्टी बांधकर काम किया। दअरसल अपनी अलग-अलग मांगों को लेकर प्रदेशभर के सरकारी डॉक्टरों ने एकजुट होकर आंदोलन करने का ऐलान किया है। आंदोलन की शुरुआत राजधानी भोपाल के हमीदिया अस्पताल के ब्लॉक-2 के सामने हुई, जहां डॉक्टर्स ने विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में मेडिकल ऑफिसर्स, चिकित्सा शिक्षक, चिकित्सक और जूनियर डॉक्टर शामिल रहे। चिकित्सक महासंघ ने अपनी प्रमुख मांगों में उच्च न्यायालय द्वारा आदेशित उच्च स्तरीय समिति का गठन, कैबिनेट से पारित डीएसीपी और एनपीए का सही क्रियान्वयन, सातवें वेतनमान का वास्तविक लाभ और चिकित्सा क्षेत्र में प्रशासनिक दखलंदाजी को रोकने जैसी मांगें शामिल की हैं। डॉक्टरों ने सरकार से

जल्द से जल्द इन मुद्दों पर निर्णय लेने की मांग की है, अन्यथा आंदोलन और तेज करने की चेतावनी दी है।

पुरानी मांगो को पूरी करने के लिए कर रहे विरोध

चिकित्सक महासंघ के मुख्य संयोजक डॉ. राकेश मालवीया ने कहा कि यह आंदोलन प्रदेश के 52 जिला अस्पतालों, कम्युनिटी अस्पतालों, सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और मेडिकल कॉलेजों के डॉक्टरों द्वारा किया जा रहा है। डॉ. मालवीया ने कहा कि यह आंदोलन किसी नई मांग को लेकर नहीं है। हमारी पुरानी मांगें आज भी वैसी ही बनी हुई हैं। इनमें से कुछ मांगों पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेश भी जारी किए जा चुके हैं, लेकिन उनका क्रियान्वयन अभी तक नहीं हुआ है। इसके अलावा, कैबिनेट से पारित डीएसीपी का भी डॉक्टरों को पूरा लाभ नहीं मिला है। सरकार को इन सभी मुद्दों पर जल्द निर्णय यू लेना चाहिए और आदेश जारी करने चाहिए, जिससे हमारा आंदोलन समाप्त हो सके। हमारा मकसद केवल न्याय पाना है, आंदोलन करना नहीं।

आगे ऐसे चलेगा आंदोलन

21 फरवरी- प्रदेश के समस्त चिकित्सक कार्यस्थल (समस्त जिला अस्पताल, ईएसआई अस्पताल, मेडिकल कॉलेज) पर काली पट्टी लगाकर काम करेंगे एवं अमानक दवाईयो की प्रतीकात्मक होली दहन करेंगे।

22 फरवरी- प्रदेश के समस्त चिकित्सक सामूहिक उपवास रखेंगे एवं मास्क पहनकर भोजन अवकाश में दोपहर आधा घंटे 12-30 से 1-00 तक अपने कार्यस्थल के बाहर विरोध प्रदर्शन करेंगे ।

24 फरवरी- प्रदेश के समस्त चिकित्सक दोपहर 12-30 से 1 -30 तक 1 घंटे तक कार्यस्थल के बहार प्रदर्शन करेंगे।

25 फरवरी- प्रदेशव्यापी उग्र आंदोलन प्रारंभ किया जाएगा।

अब निजी अस्पतालों के डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ की जानकारी ऑनलाइन पोर्टल पर

राजधानी भोपाल समेत प्रदेशभर में फर्जी अस्पताल और नर्सिंग होम्स चलने के मामले सामने आ रहे हैं। लगातार आरोप लग रहा था कि ज्यादातर निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम कम स्टाफ से संचालित हो रहे हैं। एनएसयूआई ने डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ की जानकारी ऑनलाइन करने की मांग उठाई थी जिसे विभाग ने मान ली है।

अब मध्यप्रदेश में सभी नर्सिंग होम (अस्पतालों) के डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ की जानकारी ऑनलाइन पोर्टल पर सार्वजनिक कर दी गई है। दरअसल एनएसयूआई प्रदेश उपाध्यक्ष रवि परमार ने 31 जनवरी को इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाते हुए विरोध दर्ज कराया था कि प्रदेश के अस्पतालों से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी ऑनलाइन पोर्टल से हटा दी गई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि यह कदम गड़बड़ी और अनियमितताओं को छिपाने के लिए उठाया गया, जिससे आम जनता और स्वास्थ्य सेवाओं की पारदर्शिता पर असर पड़ा। परमार ने कहा कि एनएसयूआई के दबाव और जनहित में उठाई गई आवाज के बाद गुरुवार से फिर से सभी अस्पतालों के डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ की जानकारी पोर्टल पर सार्वजनिक कर दी गई है। उन्होंने इसे मध्यप्रदेश के जागरूक नागरिकों और एनएसयूआई की बड़ी जीत करार दिया है। रवि परमार ने स्पष्ट किया कि यह केवल पहली जीत है और जब तक फर्जी अस्पताल संचालकों एवं उन्हें मान्यता देने वाले सीएमएचओ डॉ प्रभाकर तिवारी और भ्रष्ट अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई नहीं होती , तब तक एनएसयूआई का पोल-खोल अभियान जारी रहेगा आगे इस मामले में एनएसयूआई द्वारा एक अलग टीम गठित कर जाँच करेंगी जिसमें साफ हो जाएगा कि पोर्टल पर अस्पतालों द्वारा सही जानकारी अपलोड की गई है या नहीं। एनएसयूआई लगातार फर्जी अस्पतालों और भ्रष्टाचारियों को बेनकाब करता रहेगा और छात्रों व आम जनता के अधिकारों के लिए संघर्ष जारी रखेगा ।

स्वास्थ्य विभाग का वर्ल्ड क्लास स्वास्थ्य सुविधाएं देने का दावा

जीआई समिट में मेहमानों के लिए 300 से ज्यादा डॉक्टर रहेंगे तैनात

सिटी चीफ इंदौर।

भोपाल। राजधानी भोपाल में 24 व 25 फरवरी को होने जा रही ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (जीआई समिट) कार्यक्रम के दौरान स्वास्थ्य विभाग वर्ल्ड क्लास स्वास्थ्य सुविधाएं देने का दावा कर रहा है। इस दौरान 300 से ज्यादा डॉक्टर पैरामेडिकल स्टाफ मौजूद रहेंगे। विभाग ने बड़े पैमाने पर चिकित्सा व्यवस्थाएं की गईं है। समिट में आने वाले अतिथियों के लिए प्रत्येक बिंदु पर समीक्षा कर व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। मुख्य कार्यक्रम स्थल पर अत्याधुनिक चिकित्सा यूनिट बनाई जा रही है। यहां पर आईसीयू बेड्स, कार्डिएक डिफिब्रिलेटर, ऑक्सीजन, ईसीजी, मल्टीपेरा मॉनिटर, बीपी एंड ब्लड ग्लूकोज सहित तमाम आवश्यक चिकित्सा व्यवस्थाएं की गई हैं। कार्यक्रम स्थल व टेंट सिटी में पैथोलॉजिकल जांच की व्यवस्था रहेगी। आकस्मिक चिकित्सा स्थितियों में उपचार के लिए वरिष्ठ चिकित्सकों का दल तैनात रहेगा। शासकीय और निजी चिकित्सा संस्था स्तर पर भी तैयारियां सुनिश्चित की गई हैं।

एयरपोर्ट, होटल और कार्यक्रम स्थल पर मौजूद रहेगी टीम

ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में 24 एवं 25 फरवरी को आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव सहित वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री , अधिकारीगण, मल्टीनेशनल कंपनियों के प्रतिनिधि , उद्योगपति एवं गणमान्य नागरिक शामिल होंगे। जिला प्रशासन और पुलिस के साथ समन्वय कर एयरपोर्ट, होटल्स एवं कार्यक्रम स्थल पर चिकित्सक दल, चिकित्सा उपकरणों सहित एम्बुलेंसेज मौजूद रहेंगी। इसमें स्वास्थ्य विभाग की टीम सहित निजी क्षेत्र से अपोलो सेज हॉस्पिटल, सागर मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल, बंसल अस्पताल, एल एन मेडिकल कॉलेज, चिरायु मेडिकल कॉलेज, नोबेल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नर्मदा ट्रॉमा सेंटर, आरकेडीएफ मेडिकल कॉलेज, पीपल्स मेडिकल कॉलेज, कैरियर एवं हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर इत्यादि की टीम 23 से 25 फरवरी के बीच चिकित्सा सेवाओं के लिए तैनात रहेंगी। एयरपोर्ट, होटल्स, टेंट सिटी एवं कार्यक्रम स्थल को आकस्मिक चिकित्सा के लिए विभिन्न अस्पतालों के साथ टैग किया गया है। जिनके कंटेंजेसी हॉस्पिटल निकटस्थ निजी अस्पताल व फिनिटिव अस्पताल अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और हमीदिया अस्पताल होंगे।

पीएम श्री एयर एम्बुलेंस रहेगी तैयार

समिट के दौरान 23 से 26 फरवरी के बीच पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सर्विसेज आकस्मिक स्थिति के लिए एयर एम्बुलेंस तैयार रखेंगी। भोपाल जिले में संचालित सभी 108 एम्बुलेंस तथा उनके उपकरणों की क्रियाशीलता सुनिश्चित की गई है। आवश्यक होने पर अन्य जिलों की 108 एम्बुलेंस भी स्टैंडबाय मोड पर तैयार रहेंगी। निजी एवं शासकीय अस्पतालों में चिकित्सकों, पैरामेडिकल स्टाफ, सपोर्ट स्टाफ की उपलब्धता, आकस्मिक स्थिति हेतु पर्याप्त संख्या में बेड्स की व्यवस्था, ऑपरेशन थिएटर, विभिन्न समूह के रक्त की व्यवस्था, जीवन रक्षक उपकरणों, औषधियां,ऑक्सीजन,वेंटीलेटर, एचएफएनसी, सीपेप, एम्बुलेंस की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है।

सभी स्वास्थ्य संस्थाएं रहेंगी हाई अलर्ट मोड

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भोपाल डॉ. प्रभाकर तिवारी ने बताया कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए सभी स्वास्थ्य संस्थाओं को हाई अलर्ट मोड रखा गया है। अस्पतालों में चिकित्सकों, पैरामेडिकल स्टाफ, उपकरण, एम्बुलेंस, ऑपरेशन थिएटर, वेंटिलेटर, एचएफएनसी, सीपेप, विद्युत व्यवस्था सुनिश्चित की गई हैं। सभी व्यवस्थाओं के समन्वय हेतु नोडल अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। एयरपोर्ट, कार्यक्रम स्थल व होटल्स के अलावा पार्किंग स्थलों व रास्ते के मुख्य चौराहों पर भी एंबुलेंस तैयार रहेंगी। यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि आवश्यकता होने पर 1 से 4 मिनट में आकस्मिक सेवा एवं एंबुलेंस उपलब्ध हो सके।

लांबाखेड़ा में बंद कमरे में मिली महिला की लाश, खुदकुशी की आशंका

सिटी चीफ इंदौर।

भोपाल। भोपाल के लांबाखेड़ा में बंद कमरे में महिला की लाश मिली है। महिला की मौत संदिग्ध हालात में हुई। वह अकेली रहती थी, शादी के एक साल बाद ही पति से अलग हो चुकी थी। भोपाल में रहकर समूह लोन दिलाने का काम करती थी। वहीं, पुलिस मामले को खुदकुशी का केस मानकर चल रही है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। आरती कुशवाह (24) पुत्री मूलचंद कुशवाह लांबाखेड़ा में किराए से रहती थी। मूल रूप से विदिशा के कड़ैया खेड़ा गांव की रहनी वाली थी। 2020 में शादी हुई थी, एक साल बाद ही पति से अलग हो गई थी। परिवार से अलग ईटखेड़ी के लांबाखेड़ा में रह रही थी। बुधवार को दिन भर कार्यालय वाले उसे कॉल करते रहे। कॉल नहीं उठाया तो उसके परिजनों को इस बात की जानकारी दी गई। सूचना के बाद भोपाल में रहने वाले उसके जीजा ने लांबाखेड़ा में स्थित उसके कमरे पर पहुंचकर चेक किया। काफी आवाजें देने पर भी गेट नहीं खुला, तब गेट को तोड़कर अंदर प्रवेश किया। यहां जमीन पर आरती का शव अचेत अवस्था में देखा गया। इसके बाद में पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस की शुरुआती जांच में पॉइजन खाकर सुसाइड की बात सामने आई है। पुलिस को कमरे से संदिग्ध जहरीला पदार्थ भी मिला है। हालांकि परिजनों ने पुलिस को खुदकुशी के लिए कोई ठोस वजह नहीं बताई है। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस महिला की मौत संदिग्ध हालात में होना मानकर चल रही है।

नवविवाहिता ने फांसी लगाकर दी जान, 12 दिन बाद थी एनिवर्सरी

सिटी चीफ इंदौर।

भोपाल। भोपाल के छोला मंदिर इलाके में रहने वाली नवविवाहिता ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस को मृतका के पास से सुसाइड नोट नहीं मिला है। वहीं लड़की की मां ने दामाद की प्रताड़ना से तंग आकर बेटी द्वारा खुदकुशी करने के आरोप लगाए हैं। घटना बुधवार की देर रात की है, गुरुवार की सुबह पीएम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। काजल गुप्ता (20) गोली गुप्ता शंकर नगर उड़िया बस्ती छोला की रहने वाली थी। वह गृहिणी थी और उसका पति ऑटो चालक है। 4 मार्च 2024 को उसकी शादी हुई थी। 12 दिन बाद उसकी पहली एनिवर्सरी आने वाली थी। मृतका की मां नीतू गुप्ता ने बताया कि शादी के बाद से ही दामाद बेटी को परेशान करता था। उस पर मायके से अलग-अलग सामान दिलाने का दबाव बनाता था। पिछले दिनों उसे एक मोबाइल फोन दिलाया था, अब गाड़ी की मांग करने लगा था। इसी बात को लेकर बेटी को प्रताड़ित करता था। नीतू ने बताया कि बेटी का कॉल बुधवार की दोपहर को आया था। तब उसने दामाद द्वारा आए दिन बदसलूकी करने और मायके से पैसा लाने का दबाव बनाने की बात कही थी। रात को दामाद का कॉल आया, उसने बताया कि काजल कुछ बोल नहीं रही है। उसकी तबीयत बहुत खराब है, जब अस्पताल पहुंचे तो बेटी के शव को देखा।

रिसेप्शन से पहले दूल्हे के सामने प्रेमी के साथ भागी दुल्हन, तलाश में जुटी पुलिस

सिटी चीफ इंदौर।

भोपाल। गंजबासौदा निवासी एक युवती की 18 फरवरी को भोपाल निवासी आशीष रजक के साथ शादी हुई है। 19 फरवरी को भोपाल के टीटी नगर थाना क्षेत्र स्थित एक मैरिज गार्डन में वर पक्ष की तरफ से रिसेप्शन रखा गया था। दुल्हन अपनी ननद के साथ ब्यूटी पार्लर में मेकअप कराने गई थी, वहां से लौटकर वह रिसेप्शन वाले मैरिज गार्डन के सामने कार से पहुंची और कार से उतरकर वह पास में खड़ी दूसरी कार से फरार हो गई। दुल्हन के इंतजार में गार्डन के बाहर खड़ा दूल्हा देखता ही रह गया। दूल्हे की शिकायत पर टीटी नगर थाना पुलिस ने दुल्हन की तलाश शुरू कर दी है, उसकी अंतिम लोकेशन विदिशा में मिली। उसके सागर और विदिशा के मध्य कहीं छिपे जोने की आशंका है। थाना प्रभारी सुधीर अरजरिया ने बताया कि गुमशुदगी का प्रकरण दर्ज कर जांच की जा रही है। दुल्हन के मोबाइल की कॉल डिटेल निकाली तो पता चला कि वह मायके गंजबासौदा में पड़ोस में रहने वाले अनिकेत मालवीय से चार-पांच साल से दोस्ती थी। शादी के बाद भी अनिकेत मालवीय के साथ दुल्हन की कई बार मोबाइल पर बात हुई है। दुल्हन ने अनिकेत और उसके दोस्त राहुल व अशफाक के साथ कार से आया था और सहमति से दुल्हन अनिकेत के साथ कार से गई है। अशफाक वाहन चला रहा था। दुल्हन की तलाश में विदिशा, गंजबासौदा व सागर में पुलिस की टीम छापेमारी कर रही है। दुल्हन व उसके परिजन का मोबाइल बंद आ रहा है। पुलिस परिजनों से संपर्क कर हकीकत पता लगाने में जुटी है।

धीरेंद्र शास्त्री पर बयान देकर अकेले पड़े कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक

सिटी चीफ इंदौर।

भोपाल। मध्यप्रदेश कांग्रेस के मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को लेकर विवादित बयान देकर अकेले पड़ गए हैं। जहां एक तरफ जहां भाजपा सनातन के अपमान का आरोप लगाते हुए कांग्रेस को घेर रही है, तो वहीं कांग्रेस नेता भी उनके बयान से सहमत नहीं हैं। पूर्व मंत्री कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने गुरुवार को पीसीसी में मीडिया के सवाल पर कहा कि यह निजी आस्था का विषय है। मेरी महराज जी से पुरानी पहचान है। यह उनका निजी बयान है। जानकारी के अनुसार मुकेश नायक के बयान पर पार्टी के पदाधिकारी भी नाराज हैं। गौरतलब है कि जहां कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को उचक्का तक कह दिया है। वहीं मध्य प्रदेश विधान सभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार कुछ दिन पहले ही बागेश्वर धाम पहुंच कर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से मुलाकात की थी। वहीं पूर्व सीएम कमलनाथ ने तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की छिंदवाड़ा में कथा का आयोजन कर चुके हैं। कई कांग्रेस नेता उनसे मिलने जाते रहेते हैं। दरअसल बागेश्वर धाम ट्रस्ट द्वारा बनाए जा रहे कैंसर हॉस्पिटल के भूमिपूजन के लिए 23 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी छतरपुर पहुंच रहे हैं. इस कार्यक्रम में देशभर के बड़े साधु संतों को भी आमंत्रित किया गया है। इधर, भूमिपूजन से पहले बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पं.धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को लेकर मध्यप्रदेश की सियासत गर्मा गई है। दरअसल, धीरेन्द्र शास्त्री पर मध्यप्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने आपत्तिजनक टिप्पणी की है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव समेत बीजेपी कई बड़े नेता कांग्रेस पार्टी को घेर रही है। अब कांग्रेस नेता इसे निजी बयान बता रहे हैं।

सिंहस्थ-2028 में एआई से चलेंगी गोल्फ कार्ट और मिनी बसें

सिटी चीफ इंदौर।

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सिंहस्थ-2028 के प्रबंधन में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस सहित नवीनतम तकनीकों के उपयोग की संभावनाओं पर विचार-विमर्श के लिए मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन में बैठक आयोजित की गई। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बैठक में प्रेजेंटेशन देखा। बैठक में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए एआई आधारित गोल्फ कार्ट, मिनी बसों और 9 मीटर लंबी बसें चलाने पर चर्चा हुई। प्रेजेंटेशन में आईआईटी एल्यूमिना काउंसिल के सतीश मेहता ने सुझाव दिया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित सोलर गोल्फ कार्ट्स और इलेक्ट्रिक मिनी बसें इंदौर, देवास और ओंकारेश्वर से सीधे उज्जैन पहुंचे श्रद्धालुओं को शिप्रा नदी घाट तक पहुंचाने में मदद कर सकती हैं। इससे लोगों को कम दूरी तय करनी पड़ेगी और यात्रा सुविधाजनक होगी। मुख्यमंत्री ने इस प्रस्ताव पर कहा कि सिंहस्थ एक बड़ा मेला है, जिसमें हमेशा भीड़ और व्यवस्था की समस्याएं रहती हैं। इसे चलाने के लिए हमें इसे पहले छोटे स्तर पर परीक्षण करना होगा, फिर ही हम आगे का निर्णय ले सकते हैं। उन्होंने इंदौर में इस ट्रायल को आयोजित करने के निर्देश दिए। सिंहस्थ के आयोजन को देखते हुए मुख्यमंत्री ने इस बार विशेष रूप से भीड़ प्रबंधन, आवास, पार्किंग, स्वच्छता और पेयजल व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करने की बात की। साथ ही, उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सिंहस्थ-2028 को श्रद्धालुओं के लिए अविस्मरणीय बनाने के लिए सभी व्यवस्थाओं का समुचित प्रबंधन किया जाए। इसके तहत सूचना प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, सिंहस्थ के आयोजन में विद्युत आपूर्ति को बेहतर बनाने के लिए उज्जैन में छह नए ग्रिड स्थापित किए जाएंगे। इस उद्देश्य से मप्र पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी और ट्रांसमिशन कंपनी के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए त्रिवेणी विहार, चिंतामण, हासमपुरा और अन्य क्षेत्रों में नए ग्रिडों का निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी सुनिश्चित किया कि सिंहस्थ-2028 के आयोजन में हर पहलू पर ध्यान दिया जाएगा, ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े।

सम्पादकीय

ओटीटी पर अश्लील कंटेंट को लेकर सरकार हुई सख्त

केंद्र सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को लेकर एक एडवाइजरी जारी की है। जिसमें कंटेंट के आयु-आधारित वर्गीकरण को सख्त करने और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) नियम 2021 का अनुपालन करने का आग्रह किया गया है। यह एडवाइजरी समय रैना के यूट्यूब शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट' के एक एपिसोड को लेकर विवाद के बाद आई है। जिसमें रणवीर अल्लाहबादिया ने अनुचित टिप्पणी की थी। जिसको लेकर काफी विवाद गहरा गया था।

केंद्र सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को लेकर एक एडवाइजरी जारी की है। जिसमें कंटेंट के आयु-आधारित वर्गीकरण को सख्त करने और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) नियम 2021 का अनुपालन करने का आग्रह किया गया है। यह एडवाइजरी समय रैना के यूट्यूब शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट' के एक एपिसोड को लेकर विवाद के बाद आई है। जिसमें रणवीर अल्लाहबादिया ने अनुचित टिप्पणी की थी। जिसको लेकर काफी विवाद गहरा गया था। हालांकि, अब यह मामला कोर्ट की चौखट पर है। हाल ही में यूट्यूब के एक कथित कॉमेडी शो से उठे राष्ट्रव्यापी विवाद के बाद आरोपी यूट्यूबर को गिरफ्तारी से राहत देते व सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणियां की हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में आरोपी से कहा कि उसने अपने दिमाग में भरी गंदगी को उगला है। अदालत ने रणवीर इलाहाबादिया के बयान पर कठोर टिप्पणी करते हुए कहा कि उसकी बातों से बेटियों, बहनों और माता-पिता को भी शर्मिंदगी उठानी पड़ी है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह ने केंद्र सरकार से पूछा कि वह सोशल मीडिया पर अश्लीलता रोकने की योजना बताएं। अन्यथा इस मामले में कोर्ट देखेगा। उल्लेखनीय है कि यूट्यूबर और कॉमेडियन समय रैना के एक शो 'इंडियाज गॉट टेलेंट' के एक एपिसोड को लेकर पिछले दिनों खासा विवाद हुआ। जिसको लेकर पूरे देश में तल्ख प्रतिक्रिया सामने आई। कई राज्यों में अश्लील टिप्पणी करने वाले यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया के खिलाफ मामले दर्ज किए गए। दरअसल, रणवीर ने एक प्रतिभागी से उसके माता-पिता के निजी संबंधों को लेकर आपत्तिजनक सवाल किए थे। इस अमर्यादित व अश्लील टिप्पणी को लेकर देशव्यापी आलोचना की जा रही है। कालांतर यूट्यूब को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नोटिस के बाद इस एपिसोड को हटाना पड़ा था। दरअसल सोशल मीडिया पर ऐसी अश्लील व अभद्र टिप्पणी करने का यह पहला मामला नहीं है। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर अनाप-शनाप बकने का सिलसिला पिछले लंबे समय से सोशल मीडिया पर चल रहा है। दरअसल, कई कॉमेडियन व कलाकार विभिन्न कार्यक्रमों में ऐसी अनर्गल प्रलाप करते रहते हैं ताकि उन्हें नकारात्मक चर्चा से व्यापक पहचान मिल सके। लगातार कोशिश होती रहती है कि वर्जित विषयों को कार्यक्रमों में शामिल करके तरह-तरह के विवाद खड़े किए जाएं। दरअसल, टीवी चैनल भी टीआरपी के गंदे खेल में ऐसे हथकंडे अपनाने से नहीं चूकते, जो विवाद पैदा करें। ऐसे कॉमेडी कार्यक्रमों की लंबी श्रृंखला है जो अश्लीलता, फूहड़ता और अभद्रता को अपने विषय वस्तु बनाते हैं। पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्मों पर वर्जना तोड़ते कार्यक्रमों की बाढ़ सी आई हुई है। विडंबना यह है कि सोशल मीडिया में संपादक नामक संस्था का कोई स्थान नहीं है। इसके चलते अभिव्यक्ति की आजादी की दुहाई देकर तमाम वर्जित विषयों व संवादों को तरजीह दी जा रही है। एक हकीकत यह भी है कि अभद्र, अश्लील, आपत्तिजनक और पोर्नोग्राफिक कंटेंट से सोशल मीडिया कंपनियों को भी मुनाफा होता है। कार्रवाई की मांग किए जाने पर ये विदेशी कंपनियां अमेरिकी कानून को अपना कवच बनाने का प्रयास करती हैं। विगत में भी एक विवाद के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने सभी डिजिटल कंपनियों को शिकायत अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए थे। यद्यपि आईटी मंत्रालय को आपत्तिजनक एप्स और कंटेंट को ब्लॉक करने का अधिकार है। लेकिन इसके बावजूद सोशल मीडिया की निरंकुश भूमिका को देखते हुए एक सख्त कानून की जरूरत महसूस हो रही है। इसके अभाव में ऐसे विवादित कार्यक्रम सुर्खियों में आते रहते हैं। हो-हल्ला होने के बाद प्राथमिकी दर्ज होती है, लेकिन बहुत कम मामलों में आरोपियों को सजा हो पाती है। उन्हें कानूनी संरक्षण देने वाले भी खुलकर सामने आते हैं। यही वजह है रणवीर इलाहाबादिया वाले मामले में शीर्ष अदालत ने उनको लेकर सख्त टिप्पणियां की हैं। नीति-नियंताओं को इस सामाजिक प्रदूषण को रोकने के लिये कारगर कानून बनाने होंगे ताकि आरोपियों को समय से सजा मिल सके।

भ्रष्टाचार मिटाने के लिए नेताओं-नौकरशाहों की जिम्मेदारी जरूरी

एक के बाद एक भ्रष्टाचार के मामले सामने आते रहते हैं, पर कोई राजनीतिक दल यह दावा नहीं करता कि उनके शासित राज्य से भ्रष्टाचार पूरी तरह समाप्त हो चुका है। राज्य तो दूर की बात है कि बल्कि किसी दल में इतना भी साहस नहीं है कि यह कह सके कि कोई एक विभाग पूरी तरह भ्रष्टाचार से मुक्त है। फिर विभाग चाहे केंद्र सरकार के हों या राज्यों की सरकारें। यह निश्चित है कि भ्रष्टाचार इस देश से तब तक नहीं मिटेगा जब तक नेताओं की कथनी और करनी में अंतर रहेगा। नेताओं के साथ नौकरशाहों की भी जिम्मेदारी तय किए बगैर भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ना असंभव है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में कहा था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए एजेंसियों को खुली छूट दे दी है और इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भ्रष्टाचार एक दीमक है जिसने देश को खोखला कर दिया है और वह देश को इस बुराई से मुक्त करने के लिए पूरे मनोयोग से काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के इस दृढ़निश्चय के बावजूद भारत में भ्रष्टाचार कैंसर की तरह फैलता जा रहा है। केंद्र की भाजपा सरकार हो या राज्यों में विपक्षी दलों की सरकारें, सभी भ्रष्टाचार के विरुद्ध बड़े दावे-वादे करती रहीं हैं, किन्तु यह समस्या सुरसा के मुंह की तरह विकराल होती जा रही है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स-2024 की भ्रष्टाचार की सूची वाले देशों में भारत 96वें पायदान पर पहुंच गया है। साल 2023 में भारत की रैंक 93 थी।

भारत इस सूची मे पड़ोसी देशों की ज्यादा बुरी हालत पर कुछ राहत महसूस कर सकता है। भ्रष्टाचार की इस सूची में भारत के पड़ोसी देशों में पाकिस्तान 135 नंबर पर और श्रीलंका 121 पर हैं, जबकि बांग्लादेश की रैंकिंग और भी नीचे 149 पर चली गई है। इस लिस्ट में चीन 76वें स्थान पर है। डेनमार्क सबसे कम भ्रष्ट राष्ट्र होने की सूची में सबसे ऊपर है, उसके बाद फिनलैंड और सिंगापुर हैं। 1995 से 2024 तक भारत में भ्रष्टाचार की औसत दर 78.03 रही, जो 2024 में 96.00 के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई और 1995 में 35.00 के रिकॉर्ड निम्नतम स्तर पर पहुंच गई थी।

भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक यानी सीपीआई दुनिया में सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली वैश्विक भ्रष्टाचार रैंकिंग है। यह मापता है कि विशेषज्ञों और व्यवसायियों के अनुसार प्रत्येक देश का सार्वजनिक क्षेत्र कितना भ्रष्ट है। प्रत्येक देश का स्कोर 13 विभिन्न भ्रष्टाचार सर्वेक्षणों और आकलनों से प्राप्त कम से कम 3 डेटा स्रोतों लिया जाता है। ये सोर्स विश्व बैंक और विश्व आर्थिक मंच सहित विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा एकत्र किए जाते हैं। सीपीआई की गणना करने की प्रक्रिया की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जारी की जाने वाली सूची यथासंभव मजबूत और सुसंगत है या नहीं। भारत में विदेशी निवेश अपेक्षाकृत नहीं आने का एक प्रमुख कारण भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार के कारण भारत की अंतरराष्ट्रीय साख कमजोर है। विदेशी कंपनियां यहां निवेश करने से कतराती हैं। देश के उद्योगपति और लघु व मध्यम व्यवसायी इसकी मार से बच नहीं सके हैं। भारत एक तरफ वैश्विक ताकत बनने की दिशा में अग्रसर है, वहीं दूसरी तरफ भ्रष्टाचार की जंजीर इसके बढ़ते कदम को रोक रही है। ऐसा देश का शायद ही कोई चुनाव होगा जिसमें प्रधानमंत्री मोदी भ्रष्टाचार का जिक्र नहीं किया हो। मोदी ने लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव के दौरान भ्रष्टाचार पर प्रहार करने में कसर बाकी नहीं रखी। संसद में दिए गए भाषण में उन्होंने कहा था कि मेरे लिए भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई चुनावी जीत या हार के पैमाने पर नहीं है। मैं चुनाव जीतने या हारने के लिए भ्रष्टाचार से नहीं लड़ रहा हूं। यह मेरा मिशन है, मेरा विश्वास है। मेरा मानना है कि भ्रष्टाचार एक ऐसा दीमक है जिसने देश को खोखला कर दिया है। मैं इस देश को भ्रष्टाचार से मुक्त करने और आम लोगों के मन में भ्रष्टाचार के खिलाफ नफरत पैदा करने के लिए पूरे दिल से काम कर रहा हूं।

प्रधानमंत्री के देश से पूरी तरह भ्रष्टाचार के खात्मे के प्रति प्रतिज्ञा लेने के बावजूद यदि यह संक्रामक रोग की तरह बढ़ता ही जा रहा है तो इसके लिए ज्यादातर राजनीतिक दल जिम्मेदार हैं। क्षेत्रीय दलों की हालत यह है कि उनका एकमात्र मकसद किसी भी हालत में सत्ता में बने रहना है।

इसके लिए बेशक भ्रष्टाचार से किसी भी हद तक समझौता क्यों न करना पड़े। यही वजह रही है कि इंडिया गठबंधन लगातार चुनावों में शिकस्त खाता रहा है। आश्चर्य यह है कि लोकसभा चुनावों और राज्यों के विधानसभा चुनावों में करारी हार के बावजूद विपक्षी दलों ने भ्रष्टाचार को कभी भी प्रमुख चुनावी मुद्दा नहीं बनाया। भ्रष्टाचार को लेकर हालात ये हैं कि जैसे ही कोई भी विपक्षी दल भ्रष्टाचार का जिक्र करता है, तत्काल सत्तारुढ़ दल न सिर्फ उसके बचाव में उतर आता है बल्कि विपक्षी दल के कारनामे गिनाने लगता है। यही वजह है कि क्षेत्रीय दल अपने राज्यों में मनमानी करने पर आमदा हैं। यदि केंद्रीय जांच ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय कोई कार्रवाई करता है तो राज्य के सत्तारुढ़ दल इसे बदले की कार्रवाई करार देने लगते हैं। इसका उदाहरण पश्चिमी बंगाल की ममता बनर्जी सरकार, तमिलनाडु की स्टालिन सरकार और कर्नाटक की सिद्धरमैया की सरकार है। इतना ही नहीं राजनीतिक दलों का भरसक प्रयास होता है कि अदालतों में चल रहे भ्रष्टाचार के मामलों को भी प्रभावित किया जाए।

गौरतलब है कि सीनियर वकील हरीश साल्वे सहित देश के 600 से ज्यादा वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ को पत्र लिखकर न्यायपालिका पर सवाल उठाने को लेकर चिंता जाहिर की थी। सीजेआई को लिखी चिट्ठी में वकीलों ने कहा था कि ये समूह न्यायिक फैसलों को प्रभावित करने के लिए दबाव की रणनीति अपना रहा है, और ऐसा खासकर सियासी हस्तियों और भ्रष्टाचार के आरोपों से जुड़े मामलों में हो रहा है। चिट्ठी में कहा गया है कि ये समूह ऐसे बयान देते हैं जो सही नहीं होते हैं और ये राजनीतिक लाभ के लिए ऐसा करते हैं। अपनी चिट्ठी में वकीलों ने ऐसे कई तरीकों पर प्रकाश डाला है, जिनमें न्यायपालिका के तथाकथित ह्यस्वर्ण युगह्ल के बारे में झूठी कहानियों का प्रचार भी शामिल है। न्यायपालिका तक को प्रभावित करने के प्रयासों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत में भ्रष्टाचार किस हद तक व्याप्त है। देश की भ्रष्टाचार में रैंकिग बेशक बढ़ रही हो, इसके बावजूद विगत चुनावों में भाजपा अकेली पार्टी रही, जिसने भ्रष्टाचार के खात्मे की बात कही। अन्य दल तो इस मुद्दे पर चर्चा करने तक से कतराते हैं। विपक्षी दलों ने केंद्र के सत्तारुढ दल को भ्रष्टाचार में लपेटने की कई बार नाकाम कोशिश की है, चाहे वह मुद्दा युद्धक विमान राफेल की खरीद का हो या अडानी ग्रुप से जुड़ा हुआ हो। विपक्षी दल सुप्रीम कोर्ट तक में भ्रष्टाचार के मामले को ले गए पर इसे साबित नहीं कर पाए। ऐसा भी नहीं है कि भाजपा भ्रष्टाचार को लेकर दूध की धुली है। भाजपा का दामन थामने वाले विपक्षी दलों के नेताओं के ऐसे मामलों को नजरांदाज किया जाता रहा है। इसके अलावा केंद्र में भाजपा अकेले अपने बलबूते सत्ता में नहीं है, ऐसे में गठबंधन के सहयोगी दलों पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों से मुंह फेरे रहती है। यही वजह रही है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से इन सहयोगी दलों के खिलाफ एक भी कार्रवाई नहीं की गई।

कोई भी एजेंसी जब किसी राज्य या विभाग में भ्रष्टाचार का मामला पकड़ती है तब इस गुनाह पर पर्दा डालने के लिए यही दलील दी जाती रही है कि भ्रष्टाचार को मिटाना है। इसके बावजूद एक के बाद एक भ्रष्टाचार के मामले सामने आते रहते हैं, पर कोई राजनीतिक दल यह दावा नहीं करता कि उनके शासित राज्य से भ्रष्टाचार पूरी तरह समाप्त हो चुका है। राज्य तो दूर की बात है कि बल्कि किसी दल में इतना भी साहस नहीं है कि यह कह सके कि कोई एक विभाग पूरी तरह भ्रष्टाचार से मुक्त है। फिर विभाग चाहे केंद्र सरकार के हों या राज्यों की सरकारें। यह निश्चित है कि भ्रष्टाचार इस देश से तब तक नहीं मिटेगा जब तक नेताओं की कथनी और करनी में अंतर रहेगा। नेताओं के साथ नौकरशाहों की भी जिम्मेदारी तय किए बगैर भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ना असंभव है।

देश में नहीं होगी अब जान बचाने वाली दवाओं की कमी

भारत में इसी साल पहले दो बल्क ड्रग पार्क गुजरात और आंध्रप्रदेश में शुरू होंगे। करीब पांच वर्ष से जारी प्रयासों के बाद थोक औषधियों और सक्रिय औषधि अवयवों (एपीआई) के आयात पर भारत की निर्भरता अब लगभग खत्म होगी। इसके साथ ही आम बजट में घोषित 36 जीवन रक्षक दवाओं को सरकार ने सीमा शुल्क से बाहर रखने का आदेश जारी करते हुए फार्मा कंपनियों से दवा मूल्य का संशोधन करने के लिए कहा है। केंद्रीय फार्मास्यूटिकल्स विभाग के अनुसार, इस साल गुजरात के भरूच और आंध्रप्रदेश के अनकापल्ली में बल्क ड्रग पार्क चालू हो जाएंगे। इसके लिए बल्क ड्रग निर्माताओं को भूमि और अन्य सुविधाएं प्रदान की गई हैं। प्रत्येक बल्क ड्रग पार्क के लिए केंद्र की ओर से करीब एक हजार करोड़ रुपये खर्च किए गए।

दरअसल बल्क ड्रग्स यानी थोक औषधियों को सक्रिय फार्मास्युटिकल अवयव (एपीआई) के रूप में जानते हैं जिनके जरिये दवाओं के फार्मूलेशन बनाने में किया जाता है। अभी तक काफी संख्या में एपीआई को बाहरी देशों से मंगाया जाता है, जिसकी वजह से दवा का उत्पादन और बाजार में उसका शुल्क अधिक हो जाता है। भारत के अलग-अलग हिस्सों में बल्क ड्रग पार्क शुरू होने के बाद यह सभी एपीआई का भारत में उत्पादन होगा और यहीं से दवाएं बनाई जाएंगी। उत्पादन लागत कम होने का सबसे बड़ा लाभ मरीजों को सस्ती दवाओं के रूप में मिलेगा। विभाग के सचिव अमित अग्रवाल ने बताया कि साल 2020 में केंद्र सरकार ने तीन बल्क ड्रग पार्क बनाने की घोषणा की। इसके चलते हमें 15 राज्यों से आवेदन प्राप्त हुए जिनकी समीक्षा के बाद गुजरात, आंध्रप्रदेश के अलावा हिमाचल प्रदेश का नाम तय हुआ। तब से यहां पार्क बनाने की गतिविधियां काफी तेजी से चल रही हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि इस साल में गुजरात और आंध्रप्रदेश के रूप में भारत को पहले दो बल्क ड्रग पार्क प्राप्त होंगे। उन्होंने कहा कि दवा उत्पादन को लेकर भारत की आत्मनिर्भरता के मामले में काफी तेजी से बदलाव हो रहे हैं। पेनिसिलिन-जी और क्लैवुलैनीक एसिड जैसी अहम एंटीबायोटिक दवाओं का उत्पादन अब भारत में होने लगा है। इसी तरह टीबी संक्रमण के उपचार में इस्तेमाल रिफैम्पिसिन दवा भी फिर से भारत में बनेगी। सचिव अमित अग्रवाल ने बताया कि बायोसिमिलर औषधियों के उभरते क्षेत्र में भारत अब वैश्विक नेता के रूप में आगे बढ़ रहा है। अभी तक 98 तरह के मंजूर बायोसिमिलर का उत्पादन भारत में होने लगा है। वहीं 40 से ज्यादा अभी क्लीनिकल परीक्षण की स्थिति में है। बायोसिमिलर औषधि एक जैविक औषधि है जो पहले से स्वीकृत जैविक औषधि के समान होती है। जीवित जीवों, जैसे कोशिकाओं या सूक्ष्मजीवों से बनाए जाते हैं। इसी तरह सालाना 54 हजार से अधिक नैदानिक परीक्षण और चार लाख से अधिक एआई संबंधित कर्मचारियों की क्षमता की बदौलत दुनिया में भारत दूसरा सबसे बड़ा एआई प्रतिभा पूल वाला देश बना है।

युवाओं में बढ़ता खतरनाक स्टंट कल्चर: जिम्मेदारी किसकी?

हाल ही में छत्तीसगढ़ के कवर्धा और अंबिकापुर में 12वीं के छात्रों द्वारा तेज रफ्तार कार और ट्रैक्टर से खतरनाक स्टंट करने की घटना सामने आई। छात्रों ने स्कॉर्पियो और बाइक पर सवार होकर स्कूल में एंट्री ली और फेयरवेल पार्टी के बाद स्कूल मैदान में भी स्टंटबाजी की। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह केवल एक मामला नहीं है, बल्कि देशभर में युवाओं द्वारा इस प्रकार के जोखिम भरे स्टंट करने की घटनाएं आम होती जा रही हैं।

समाज में एक नया ट्रेंड बन चुका है जहां युवा तेज रफ्तार गाड़ियों पर स्टंट करते हैं, बीच सड़क पर दौड़ लगाते हैं, या फिर सोशल मीडिया पर लाइक्स और व्यूज बटोरने के लिए जानलेवा करतब दिखाते हैं। यह समस्या केवल सड़कों तक सीमित नहीं है, बल्कि स्कूल और कॉलेज परिसरों में भी ऐसे दृश्य देखने को मिल रहे हैं। सवाल यह उठता है कि आखिर इन घटनाओं के पीछे जिम्मेदार कौन है? क्या यह सिर्फ युवाओं की लापरवाही और अति-उत्साह का परिणाम है, या इसके पीछे कोई गहरी सामाजिक समस्या छिपी है?

खतरनाक स्टंटबाजी का बढ़ता ट्रेंड

आजकल सोशल मीडिया के प्रभाव में युवा ऐसे स्टंट करने के लिए प्रेरित हो रहे हैं, जो न केवल उनके जीवन के लिए खतरा बन सकते हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी जानलेवा साबित हो सकते हैं। टिकटॉक, इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स जैसी प्लेटफॉर्म्स पर स्टंट वीडियो तेजी से वायरल होते हैं। इसे प्रेरित होकर अन्य युवा भी खुद को 'हीरो' साबित करने के लिए खतरनाक हरकतें करने लगते हैं।

कई मामलों में यह देखा गया है कि युवा अपने माता-पिता की महंगी गाड़ियां लेकर सड़कों पर निकलते हैं और फिल्मी स्टाइल में स्टंटबाजी करने लगते हैं। तेज रफ्तार गाड़ी चलाना, बाइक को हवा में उठाकर चलाना (व्हीली करना), कार को ड्रिफ्ट कराना और खुले ट्रकों व ट्रैक्टरों पर खतरनाक करतब दिखाना अब आम बात हो गई है।

किन कारणों से युवा स्टंट करने की ओर आकर्षित हो रहे हैं?

1. सोशल मीडिया का दबाव

आज के दौर में सोशल मीडिया पर 'वायरल' होना ही सफलता की नई परिभाषा बन गया है। युवा चाहते हैं कि उनके वीडियो वायरल हों, उनके फॉलोअर्स बढ़ें और उन्हें प्रसिद्धि मिले। इसके लिए वे अपनी जान जोखिम में डालने से भी पीछे नहीं हटते।

2. फिल्मों और वेब सीरीज का प्रभाव

बॉलीवुड और हॉलीवुड फिल्मों में दिखाए जाने वाले स्टंट युवाओं को रोमांचित करते हैं। फिल्मों में हीरो को बाइक पर खतरनाक स्टंट करते देख युवा उसे वास्तविक जीवन में

दोहराने की कोशिश करते हैं, बिना यह समझे कि फिल्मों में ये सब विशेषज्ञों की निगरानी में किया जाता है।

3. माता-पिता की लापरवाही

कई मामलों में माता-पिता खुद अपने बच्चों को महंगी और तेज रफ्तार गाड़ियां उपलब्ध कराते हैं। वे इस बात की निगरानी नहीं करते कि उनके बच्चे उन वाहनों का सही इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं। कुछ अभिभावक अपने बच्चों को 'कूल' दिखने के लिए खुद भी ऐसे व्यवहार को प्रोत्साहित करते हैं।

4. कानून व्यवस्था की लचरता

पुलिस और प्रशासन अक्सर इस तरह की घटनाओं को गंभीरता से नहीं लेते। कई बार रसूखदार परिवारों के बच्चों को पकड़ने के बाद भी छोड़ दिया जाता है। इसे युवाओं में कानून का डर खत्म हो जाता है और वे बेखौफ स्टंट करते रहते हैं।

5. दोस्तों का दबाव और ग्रुप कल्चर

कई बार युवा अपने दोस्तों के दबाव में आकर ऐसे स्टंट करते हैं। वे ग्रुप में खुद को साबित करने के लिए ऐसी खतरनाक हरकतें करते हैं, जिससे उनकी 'इमेज' बनी रहे।

क्या कहता है कानून?

भारत में यातायात नियमों के तहत स्टंटबाजी एक अपराध है। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत लापरवाही से वाहन चलाने और खतरनाक स्टंट करने पर सख्त सजा का प्रावधान है। धारा 184 के तहत लापरवाही ड्राइविंग करने पर 1,000 रुपये से 5,000 रुपये तक का जुर्माना और छह महीने से एक साल तक की कैद हो सकती है।

इसके अलावा, अगर स्टंट के कारण किसी की जान चली जाती है या गंभीर दुर्घटना होती है, तो धारा 304 के तहत गैर इरादतन हत्या का मामला भी दर्ज किया जा सकता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये कानून सख्ती से लागू किए जाते हैं?

समाज और प्रशासन की जिम्मेदारी

1. माता-पिता की भूमिका

माता-पिता को चाहिए कि वे अपने बच्चों को जिम्मेदारी से वाहन चलाने की शिक्षा दें। उन्हें यह समझाना होगा कि स्टंटबाजी केवल फिल्मों तक सीमित होनी चाहिए, वास्तविक जीवन में नहीं। बच्चों पर नजर रखना जरूरी है कि वे कौन से वीडियो देख रहे हैं, किससे प्रेरित हो रहे हैं, और किस तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रहे हैं।

2. स्कूलों और कॉलेजों की जिम्मेदारी

शैक्षणिक संस्थानों को अपने परिसरों में इस तरह की गतिविधियों को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने चाहिए। छात्रों को यातायात नियमों और स्टंटबाजी के खतरों के बारे में जागरूक करने के लिए सेमिनार और वर्कशॉप आयोजित करनी चाहिए।

3. पुलिस और प्रशासन की भूमिका

पुलिस को चाहिए कि वे ऐसे मामलों में सख्ती दिखाएं और केवल रसूखदारों के दबाव में आकर मामले को न दबाएं। स्टंटबाजी करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि अन्य युवाओं को इसे सबक मिले।

4. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी

सोशल मीडिया कंपनियों को चाहिए कि वे ऐसे कंटेंट को प्रमोट न करें जो युवाओं को खतरनाक स्टंट करने के लिए उकसाते हैं। इसके लिए स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस बनाई जानी चाहिए और ऐसे वीडियो को ब्लॉक करना चाहिए।

निष्कर्ष

युवाओं में स्टंटबाजी का बढ़ता ट्रेंड गंभीर चिंता का विषय है। यह केवल उनकी खुद की जिंदगी के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए खतरनाक है। माता-पिता, स्कूल, पुलिस और सोशल मीडिया—सभी को मिलकर इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए काम करना होगा।

युवा जीवन में उत्साह होना स्वाभाविक है, लेकिन अगर यह उत्साह जानलेवा साबित हो रहा है, तो इसे नियंत्रित करने की जरूरत है। जिम्मेदार नागरिक के रूप में हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि सड़कें केवल यात्रा करने के लिए रहें, न कि स्टंट का अखाड़ा बनें। जब तक समाज और प्रशासन मिलकर इस समस्या का समाधान नहीं निकालते, तब तक ऐसी घटनाएं बार-बार दोहराई जाएंगी और मासूम जिंदगियां खतरे में पड़ती रहेंगी।

(राजीव खरे ब्यूरो चीफ छत्तीसगढ़)

जोनल एवं सेक्टर मजिस्ट्रेट प्रतिदिन करें परीक्षा केंद्रों का भ्रमण :- डीएम मनीष बंसल

डीएम ने यूपी बोर्ड परीक्षाओं को सकुशल संपन्न कराने के लिए की बैठक

गौरव सिंघल . सिटी चीफ (उ प्र)

सहारनपुर, जिलाधिकारी मनीष बंसल की अध्यक्षता में जनमंच सभागार में आगामी बोर्ड परीक्षाओं को सकुशल, निर्विघ्न एवं शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के संबंध में बैठक आहूत की गई। बैठक में जिलाधिकारी मनीष बंसल ने कहा कि प्रत्येक स्तर से यह सुनिश्चित किया जाए कि गलती से भी गलती न हो। उन्होंने कहा कि स्टेटिक मजिस्ट्रेट की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए जिम्मेदारपूर्वक अपने दायित्वों का निर्वहन करें। उन्होंने निर्देश दिए कि जोनल एवं सेक्टर मजिस्ट्रेट प्रतिदिन रेंडमली परीक्षा केंद्रों का भ्रमण करें स्ट्रांग रूम 24 घंटे सीसीटीवी कैमरा की निगरानी में रहेगा इसलिए पावर

बैकअप की पर्याप्त व्यवस्था रखी जाए। उन्होंने कहा कि नियमों का पालन करते हुए छात्रों के साथ मधुर व्यवहार रखा जाए। उन्होंने कहा कि माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट की बोर्ड परिक्षाएं शासन के साथ-साथ इसमें बैठने वाले लाखों छात्र-छात्राओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, हमें दोनों स्तर पर कार्य करना है। सभी अधिकारी, प्रधानाचार्य, केंद्र व्यवस्थापक हर वर्ष शासन द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार बोर्ड परीक्षाओं के साथ ही विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं का सफलतापूर्वक आयोजन कराते रहे हैं। प्रशिक्षण में दिए गए दिशा-निर्देशों को अच्छे से आत्मसात करेंगे तो सकुशल परीक्षा संपन्न कराने में कोई समस्या नहीं होगी। शासन द्वारा निर्धारित एसओपी के अनुसार परीक्षा की शुचिता, पवित्रता एवं गरिमा को बनाए रखते हुए नकलविहीन एवं शांतिपूर्ण ढ़ंग से संपन्न कराना है। जिला मजिस्ट्रेट मनीष बंसल ने कहा कि उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक, 2024 के तहत गड़बड़ी करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि यू0पी0 बोर्ड परीक्षाओं को सकुशल संपन्न कराने के लिए शासन द्वारा कड़े नियम लागू किए गए हैं जिसके तहत 01 करोड़ तक का जुर्माना एवं आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। परीक्षा केंद्र से सम्बंधित कोई भी सूचना, उल्लेखनीय बात तत्काल स्टैटिक एवं सेक्टर मजिस्ट्रेट के माध्यम से कन्ट्रोल रूम या उच्चाधिकारियों को दें।

एस0एस0पी0 रोहित सिंह सजवाण ने बोर्ड परीक्षाओं के दौरान पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के प्रति आश्वसत करते हुए बताया कि सभी केंद्रों पर सब इंस्पेक्टर, आरक्षी एवं महिलाआरक्षी की तैनाती की गई है। सभी नामित मजिस्ट्रेट्स के साथ भी पुलिस अधिकारी साथ रहेंगे। इसके साथ ही यातायात व्यवस्था के लिए भी आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं। डीआईओएस रेखा सुमन ने शासन की मंशा के अनुरूप नकलविहीन परीक्षाएं संपन्न कराने के प्रति आश्वस्त करते हुए बताया कि कि 24 फरवरी से 12 मार्च तक यूपी बोर्ड परीक्षाएं होनी हैं। जिले 90 परीक्षा केंद्र बनाए गये हैं। हाईस्कूल में 37286 एवं इंटरमीडिएट 35287 परीक्षार्थी समेत कुल 72573 परीक्षार्थी परीक्षा में बैठेंगे। छात्राओं की तलाशी पुरूष शिक्षक द्वारा नहीं ली जाएगी। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन डॉक्टर अर्चना द्विवेदी, एसपी सिटी व्योम बिंदल, एसपी देहात सागर जैन, जिला विद्यालय निरीक्षक श्रीमती रेखा, जिला विद्यालय निरीक्षक द्वितीय हर्ष देव स्वामी सहित सभी जोनल मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट, स्टेटिक मजिस्ट्रेट एवं केंद्र व्यवस्थापक उपस्थित रहे।

कटनी में नेशनल हाइवे पर बस पलटी

30 यात्री सवार, कई घायल

कटनी, कटनी के कोतवाली थाना अंतर्गत द्वारा ग्राम के पास नेशनल हाइवे पर फिर एक बस हैदराबाद से प्रयागराज की तरफ जा रही अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे के वक्त बस में 25 से 30 यात्री सवार बताए जा थे। ग्रामीणों की मदद से ट्रैफिक ओर कोतवाली पुलिस बल ने सभी यात्रियों को सुरक्षित बस से बाहर निकला इस घटना में आधा दर्जन लोगों को चोटें आई है जिन्हें एबिलेश से कटनी जिला अस्पताल में भर्ती कराया है जिन्हें मामूली चोट है।

कोतवाली थाना प्रभारी आशीष

शर्मा ने बताया कि यह बस प्रयागराज महाकुंभ की तरफ हैदराबाद से आ रही थी तभी कोतवाली थाना क्षेत्र द्वारा ग्राम के पास नेशनल हाइवे पर अनियंत्रित हो पलट गई जिसमें 25 से 30 लोग सवार थे जिसमें आधा दर्जन लोग सवार लोगो को चोट आई है जिन्हें एबुलेश की सहायता से जिला अस्पताल लगाया गया जहां यात्री का उपचार करा कर सभी घायल यात्री को दूसरे बस में सवार करा हैदराबाद के लिए रवाना करा दिया गया है। इस बस हादसे में अभी तक किसी के भी हताहत होने की कोई खबर नहीं है। इस हादसे के बाद मौके पर मौजूद कोतवाली और ट्रैफिक पुलिस बल ने पलटी बस को क्रेन से उठवा सड़क पर लगे लबे जाम को खुलवाया।

कटनी में बड़वारा बीआरसी दस हजार की घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार

ईओडब्लू ने करी कार्यवाई, रंगे हाथ किया गिरफ्तार

सुनील यादव . सिटी चीफ

कटनी, कटनी जिले के बड़वारा बीआरसी को ईओडब्लू ने मान्यता ले लिए दस हजार की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। ईओडब्लू के अधिकारी कर्मचारियों ने पकड़े गए बीआरसी को पकड़ बड़वारा थाने में ला कार्यवाही की जा रही है।

जबलपुर से कटनी पहुंचे ई ओ डब्लू के डीएसपी ए बी सिंह ने बताया कि बड़वारा के फरियादी राघवेंद्र सिंह ने पांचवी कक्षा विद्यालय की मान्यता के लिए आवेदन किया था जिसके सत्यापन और मान्यता दिलाने की एवज मे बड़वारा के बीआरसी

मनोज गुप्ता ने दस हजार रूपये की रिश्वत के रूप में मांग की थी। अभी तक की शिकायत पर ईओडब्लू की टीम ने रिश्वत लेते हुए बीआरसी के अधिकारी मनोज गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल ईओडब्लू की 13 सदस्य टीम आरोपी को बड़वारा थाना लाकर कार्यवाही कर रही है।

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालबर्रा में आयोजित किया गया विदाई समारोह

दो आशा कार्यकर्ता के सेवा निवृत्त होने पर स्वास्थ्य विभाग ने दि विदाई

लकेश पंचेश्वर। सिटी चीफ

लालबर्रा, नगर मुख्यालय के शासकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालबर्रा में 20 फरवरी 2025 दिन गुरुवार को विदाई समारोह का आयोजन स्वास्थ्य विभाग के सभाहाल में आयोजित किया गया जिसमें मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ मनोज पांडे,जिला कार्यक्रम प्रबंधक विक्रम सिंह ठाकुर व खंड चिकित्सा अधिकारी श्री डॉ रित्विक पटेल प्रमुख रूप से उपस्थित रहे इन लोगों कि गरिमामई उपस्थिति में कार्यक्रम कि शुरुआत हुई।

वहीं आशा कार्यकर्ता श्रीमती चन्द्रप्रभा चौधरी ग्राम बोरी व श्रीमती हामिनी नखाते ग्राम कटंगा को आशा कार्यकर्ता के पद पर से सेवानिवृत्त होने पर सम्मान व विदाई समारोह आयोजित किया गया।इस पुनीत अवसर पर उनके परिवार के सदस्य पुत्र एवं पुत्रवधु

मनीष चौधरी,ननंद प्रमिला देवी तथा हामिनी नखाते के पिता बाबूलाल तीतरमारे,पति सीताराम नखाते पुत्र मयंक नखाते भी प्रमुख रूप से उपस्थित रहे हैं।राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत श्रीमती चन्द्रप्रभा चौधरी कि न्युक्ति सत्र 2006 में ग्राम बोरी में आशा कार्यकर्ता के पद पर हुई वहीं श्रीमती हामिनी नखाते वर्ष 2006 में ग्राम कटंगा में आशा कार्यकर्ता के पद पर पदस्थ हुई इसके पुर्व सन् 1996 से वर्ष 2006 तक जनस्वास्थ्य रक्षक के रूप में भी ग्रामीणजनों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कि। वहीं उनकी इस सेवानिवृत्त होने व विदाई समारोह केअवसर पर विकासखंड कि समस्त आशा सुपरवाइजर,आशा कार्यकर्ता, सेक्टर सुपरवाइजर,ए एन एम,एम पी डब्लू, तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के समस्त कर्मचारियों द्वारा विदाई समारोह का आयोजन किया गया।

वहीं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के हस्ते शाल श्रीफल एवं भेंट देकर उनका सम्मान किया गया,खंड चिकित्सा अधिकारी द्वारा उनके कार्य से प्रेरणा लेकर सभी को कार्य करने को कहा गया एवं उनके सुखी जीवन कि कामना कि गई। वहीं विकासखंड कार्यक्रम प्रबंधक भुवनेश्वर बोपचे द्वारा उनके अनेक चुनोतियों से संघर्ष कर बेहतर स्वास्थ्य सेवा देकर समाज सेवा व मानव सेवा करने पर कार्य कि सराहना कि गई एवं उनके दिर्घायु व सुखी जीवन कि कामना कि गई।

कार्यक्रम में विकासखंड लेखा प्रबंधक संतोष दुधमोंगरें,जयकरण पंचेश्वर, श्रीमती के अजीत, डॉ धर्मेंद्र गौठिया सहित अन्य सभी कर्मचारी गण मौजूद रहे हैं।

लाखों के जेवर बरामद

माधवनगर पुलिस ने चार शातिर चोरों को पकड़ा

सुनील यादव . सिटी चीफ

कटनी, कटनी के माधवनगर पुलिस ने माधवनगर क्षेत्र में बीते दिनों हुई चार मकानों में हुई चोरी के मामले में तहकीकात करते हुए चार शातिर चोरों को पकड़ने में माधवनगर की पुलिस ने सफलता हासिल की है। पकड़े गए चोर आरोपी कटनी जिले मे माधवनगर की शुभ सिटी, दद्दा धाम सहित अन्य जगहो में भी चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया था। पकड़े गए चोरों के पास से लगभग साढे 03 लाख 50 हजार रुपए कीमत के सोने चांदी के जेवर बरामद किए गए हैं।

कटनी एसपी अभिजीत रंजन ने बताया कि माधवनगर थाना क्षेत्र दद्दाधाम ओर शुभ सिटी निवासी चार लोगों ने माधवनगर थाना के झिंझरी पुलिस चौकी में चोरी की वारदात के मामले fir दर्ज कराई थी, थाने में fir दर्ज होते ही माधवनगर की पुलिस ने इन चोर चोरों को पातासाजी करते हुए अरेस्ट किया है, अरेस्ट हुए चारों चोरों के पास से चोरी हुए 3 लाख 50 हजार रुपए के सोने चांदी के ज़ेवरात जब्त किया है। कटनी

एसपी अभिजीत रंजन ने यह भी बताया कि पकड़े गये चोरो ने पूछताछ के दौरान कटनी व सीमावर्ती जिला मैहर में भी चोरी की घटनाओ को अंजाम देने की बात कबूली है। आरोपियों के जिला कटनी में माधवनगर, कुठला, स्लीमनाबाद व जिला मैहर में आपराधिक रिकार्ड मिले है जिनके और भी आपराधिक रिकार्ड खंगाले जा रहे है।

प्रदेश में गन्ने का लाभकारी मूल्य ? 700 कुंतल गन्ना किसानों को नकद दिया जाए :- भगत सिंह वर्मा

गन्ना किसानों का गन्ने से हुआ मोह भंग :-भगत सिंह वर्मा

गौरव सिंघल . सिटी चीफ (उ प्र)

देवबंद (सहारनपुर), भाकियू वर्मा कार्यालय रविदास मार्ग पर किसानों की बैठक को संबोधित करते हुए भारतीय किसान यूनियन वर्मा व पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भगत सिंह वर्मा ने कहा कि प्रदेश की भाजपा की योगी सरकार लगातार गन्ना किसानों की घोर उपेक्षा कर रही है। गन्ना किसानों को उनकी लागत मूल्य 550 रुपए कुंतल से भी बहुत कम मात्र ?360 कुंतल चीनी मिलों से गन्ना भुगतान किया जा रहा है। जबकि पड़ोसी छोटे राज्य हरियाणा में उत्तर प्रदेश से गन्ने का मूल्य ?50 कुंतल अधिक रहता है। इस बार हरियाणा में 30 रुपए कुंतल अधिक ?400 कुंतल गन्ने का मूल्य है। जबकि वहां पर कृषि यंत्र, बीज, कीटनाशक, ट्रैक्टर, खाद आदि पर काफी छूट है। एक समय उत्तर प्रदेश के अंदर हरियाणा से अधिक गन्ना मूल्य होता था। जबकि उत्तर प्रदेश के

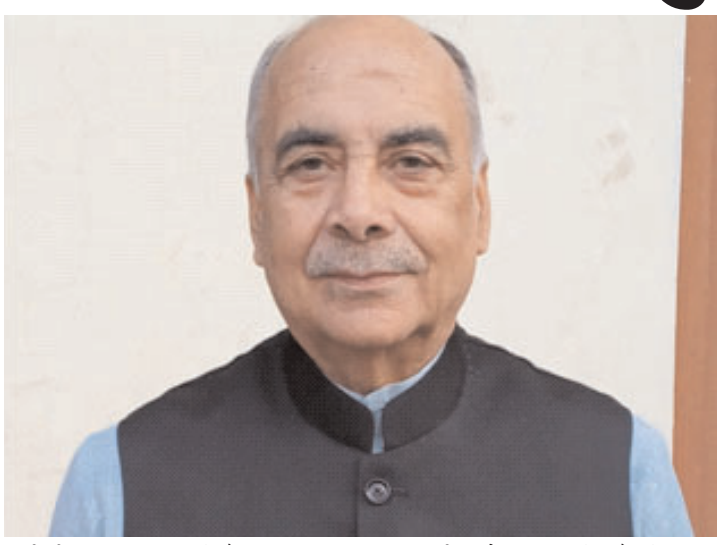

गन्ने में अधिक रिकवरी है। भगत सिंह वर्मा ने कहा कि उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों को आसानी से नकद गन्ने का लाभकारी मूल्य 700 कुंतल दिया जा सकता है। वर्ष 1967 में जब पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चौधरी चरण सिंह बने उस समय गन्ने का मूल्य 12 रूपये 10 पैसे कुंतल था। उस समय प्राइमरी स्कूल के अध्यापक की नौकरी ? 70 प्रतिमाह थी और सोने का मूल्य एक तोला 125 रुश का था आज अध्यापक की नौकरी 1000 गुना बढ़कर ?70000 प्रति माह से भी अधिक हो गई है और सोना 600 गुणा से भी अधिक बढ़ गया है। इस हिसाब से तो गन्ने का मूल्य ?12000 कुंतल बैठता है। लगातार गन्ना किसानों को गन्ने का मूल्य लागत मूल्य से भी कम मिलने पर प्रदेश के गन्ना किसानों पर बैंक सहकारी समितियां अन्य संस्थाओं का कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है। जबकि प्रदेश सरकार को प्रतिवर्ष एक्साइज ड्यूटी के रूप में गन्ने से 50 हजार करोड रुपए राजस्व प्राप्त होता है और इसके अलावा गन्ने से चीनी, शीरा, अल्कोहल से बनने वाले हजारों उत्पाद से प्रतिवर्ष प्रदेश सरकार को एक लाख करोड रुपए जीएसटी व अन्य टैक्स से राजस्व प्राप्त होता है। इसके बावजूद भी भाजपा की योगी सरकार प्रदेश के गन्ना किसानों को खोई, बगास के मूल्य के बराबर भी गन्ने का मूल्य नहीं दिला पा रही है। जिसके कारण प्रदेश के गन्ना किसानों का लगातार गन्ने से मोह भंग होता जा रहा है। गन्ना किसान मजबूरी में गन्ने के अलावा फल, सब्जी, पॉपुलर, गेहूं, धान की तरफ जा रहा है। जिससे आने वाले समय में प्रदेश सरकार को भी भारी हानि होगी और चीनी मिलों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ेगा। प्रदेश के गन्ना किसानों को आशा थी कि इस बार हरियाणा के बराबर उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों को गन्ना मूल्य मिलेगा। जिस पर मुख्यमंत्री योगी ने पानी फेर दिया है। जिसका खामियाजा भाजपा की योगी सरकार को विधानसभा के 2027 विधानसभा चुनाव में झेलना पड़ेगा। बैठक की अध्यक्षता करते हुए भारतीय किसान यूनियन वर्मा के प्रदेश उपाध्यक्ष राव शाहिद प्रधान ने कहा कि प्रदेश सरकार गन्ना किसानों को बर्बाद करने पर तुली हुई है। पहले से ही गन्ना किसानों के सामने मजदूरों का भारी संकट है। बैठक का संचालन करते हुए प्रदेश महामंत्री आसिम मलिक ने कहा कि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार को मिलकर मनरेगा योजना को सीधा खेती से जोड़कर किसानों को मजदूर उपलब्ध कराने चाहिए और गन्ने का लाभकारी मूल्य ? 700 कुंतल तत्काल गन्ना किसानों को दिलाना चाहिए। बैठक में राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष राजेंद्र चौधरी, राष्ट्रीय सलाहकार रजत शर्मा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मोहम्मद फिरोज खान, राष्ट्रीय महामंत्री रामकुमार नेताजी, प्रदेश उपाध्यक्ष पंडित नीरज कपिल, प्रदेश उपाध्यक्ष मोहम्मद जहीर तुर्की, प्रदेश संगठन मंत्री धर्मवीर चौधरी, प्रदेश सचिव ऋषिपाल गुर्जर प्रधान, मंडल मीडिया प्रभारी दुष्यंत सिंह, मंडल उपाध्यक्ष सरदार गुरविंदर सिंह बंटी, मंडल उपाध्यक्ष कृपाल सिंह, जिला उपाध्यक्ष वसीम जहीरपुर, जिला मंत्री महबूब हसन, जिला संगठन मंत्री सुरेंद्र सिंह एडवोकेट आदि ने भाग लिया।

रसुखदारी के बल पर हो रहा सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण

एसडीएम तहसीलदार मौन

तराना- स्थानीय पोस्ट ऑफिस तराना के सामने मुंगेर गली की घाटी के कोने पर सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण कार्य किया जा रहा है जिसके शिकायत पीड़ित के द्वारा नगर परिषद सीएमओ प्रभारी तहसीलदार टीना मालवीय एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व राजेश बोरासी को की है लेकिन रसूखदारी के बल पर स्थिति तथा स्थित है और कौन सुनने को तैयार नहीं है

ज्ञात रहे कि यह वही सर्वे नंबर है वही शासकीय भूमि है जिस पर रसूखदारी के बल पर वर्ष 2024 में फर्जी नामांतरण करवा लिया गया था जिसको जनप्रतिनिधि की सूझबूझ से निरस्त करवाया गया था लेकिन अब बिना किसी ठोस दस्तावेज बिना कागज बिना नामांतरण के रसुखदारी के बल पर उपरोक्त अवैध निर्माण कार्य किया जा रहा है जिसको लेकर पीड़ित यहां वहां भटक रहा है लेकिन अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। ज्ञात रहे की मुख्यमंत्री के घर जिले में इस प्रकार की वैधानिक गतिविधियां निश्चित रूप से प्रदेश और जिले को शर्मसार करने वाली घटना है ऐसे में देखना यह है कि प्रशासनिक अधिकारी क्या कदम उठाते हैं

हर मरीज को मिलेगा इलाज

नर्मदा मेडिकल बोट चलेगी, हर जरूरतमंद तक पहुंच रहा इलाज

बरेली लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल नर्मदा नदी में मेडिकल बोट चलाकर नर्मदा के मुहाने रहने वाले लोगों और नर्मदा परिक्रमा करने वालों तक चिकित्सा सुविधा पहुंचाना चाहते हैं। इसका खाका उन्होंने तैयार कर लिया है। उन्होंने खुद को मंत्री बनाए जाने पर कहा कि यह सिर्फ भाजपा में ही संभव है, जहां एक आम कार्यकर्ता को मंत्री तक बनाया गया।

प्रतिनिधि से खास चर्चा करते हुए राज्य मंत्री श्री पटेल ने कहा कि हमारा प्रयास है अंतिम छोर के व्यक्ति तक आसानी से चिकित्सा सुविधा पहुंचे। सभी शहरों में हमारी सरकार डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करा रही है। हमारा प्रयास है कि माँ नर्मदा के किनारे पर रहने वाले लोगों और नर्मदा परिक्रमा करने वाले श्रद्धालुओं तक हम चिकित्सकीय सुविधा मेडिकल बोट के जरिए पहुंचाएं। नर्मदा समग्र अभी इस तरह के प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा आजकल बड़ी संख्या में श्रद्धालु नर्मदा परिक्रमा कर रहे हैं, इसलिए हमें मेडिकल

भाजपा में ही संभव है आम कार्यकर्ता का मंत्री बनना

उज्जैन में विश्व स्तरीय फूड एंड ड्रग लैब बनेगी

बोट का विचार करना पड़ा। श्री पटेल का कहना है उनके और विभाग के मंत्री राजेंद्र शुक्ला के बीच बेहतर तालमेल है। उन्होंने मुझे तमाम कामों के साथ मुख्य रूप से फूड और ड्रग्स का जिम्मा सौंपा है। अभी हमारे पास एक मात्र लैबोरेटरी भोपाल में है। शीघ्र हम ग्वालियर, इंदौर और जबलपुर में एक-एक आधुनिक फूड एंड ड्रग लैब बना रहे हैं। उज्जैन में हम सबसे बड़ी विश्वस्तरीय तकनीकी सुविधाओं से लैस नेशनल रैफरल लैब का निर्माण कर रहे हैं। हम मोदी जी की परिकल्पना के मुताबिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर के जरिए उप स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को मजबूत कर लोगों को इलाज पहुंचा रहे हैं, कुछ सुदूर मजरे टोलों में जहां चिकित्सा सुविधा

भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति श्री पटेल ने कहा आम लोगों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आयुष्मान भारत योजना मील का पत्थर साबित हुई है। इसके लिए प्रदेश में एक हजार अस्पताल पंजीकृत किए गए हैं। इसमें भी जो लोग चोरी और गड़बड़ करते हैं वे तकनीकी मदद से पकड़े जा रहे हैं। उन्होंने कहा मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव करप्शन पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहे हैं। गड़बड़ी और भ्रष्टाचार स्वीकार नहीं है। हमारे विभाग का लक्ष्य ही जनसेवा है। नहीं है, ऐसे 89 आदिवासी क्षेत्रों में पीएम जन मन योजना से मोबाईल मेडिकल वैन के जरिए चिकित्सा सुविधा पहुंचा रहे हैं। उन्होंने कहा आने वाले समय में हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज हो जाएगा। कुल 50 मेडिकल कॉलेज एमपी में होंगे, उसके बाद चिकित्सकों और मेडिकल स्टाफ की कमी अपने आप दूर हो जाएगी। हमारा विभाग बड़े पैमाने पर नियुक्तियां कर रहा है। सबको बेहतर स्वास्थ्य मिले यह हमारा उद्देश्य है। श्री पटेल ने कहा शिक्षा विभाग के बाद उनका विभाग दूसरा सबसे बड़ा विभाग है। पिछले एक साल में काम समझा और किया। ये सेवा भाव का काम है। मुख्यमंत्री यादव और उप मुख्यमंत्री शुक्ला जी के साथ बहुत सीखने को मिल रहा है। हम तो पहली बार के मंत्री हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हम तो भाजपा के आम कार्यकर्ता के रूप में पार्टी का पक्ष रखने के लिए डिबेट में बैठते थे। पार्टी ने टिकिट दिया और पहली बार में ही विधायक बन गए। पार्टी ने पहली बार के विधायक को मंत्री बना दिया। यह सब सिर्फ और सिर्फ भाजपा में ही संभव है। जहां हमारा नेतृत्व हर कार्यकर्ता पर नजर रखता है और उसकी उपयोगिता समझ के काम देता है। भाजपा के अलावा भारत का कोई भी राजनैतिक दल अपने आम कार्यकर्ताओं को ऐसा मौका नहीं देता।

तरबूज को सब्जी के श्रेणी में रखने से किसान परेशान

बुरहानपुर - प्रगतिशील किसान संगठन के प्रतिनिधि मंडल ने गुरुवार को कलेक्टर हर्ष सिंह से मुलाकात की किसानों ने कलेक्टर को बताया कि जिले में तरबूज की फसल लिफ कर्ल वायरस से प्रभावित हुई है प्रगतिशील किसान संगठन के संरक्षक शिवकुमार कुशवाह ने कहां आज नवागत कलेक्टर का स्वागत किया साथ ही कलेक्टर को अवगत कराया कि जिले में तरबूज की फसल पर लिफ कर्ल वायरस से नुकसान अधिक पहुंचा है लेकिन सर्वे करा कर मुआवजे की मांग की गई तो कहा जा रहा है यह फलों की गिनती में नहीं आता इसे सब्जी में बताया जा रहा है ऐसा कर मुआवजा न देने की कोशिश हो रही है वही इंदौर - इच्छापुर हाईवे के निर्माण के दौरान किसानों को आवागमन में हो रही समस्या से भी अवगत कराया गया किसान सुनील महाजन ने कहा कि किसान संगठन की ओर से तरबूज उत्पादक किसानों की समस्या से अवगत कराया है वायरस का कोई इलाज नहीं इसका सर्वे हुआ लेकिन इसे सरकार फल की जगह सब्जी मान रही है किसानों के रास्ते की समस्या से भी अवगत कराया गया मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र की बॉर्डर पर जिन लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है वहां से अतिक्रमण हटाकर किसानों के लिए रास्ता निकालने की मांग की है प्रगतिशील किसान संगठन के अध्यक्ष रघुनाथ पाटिल ने कहा की इंदौर - इच्छापुर हाईवे किनारे निर्माण के दौरान कई किसान खेत से आवागमन में परेशानी उठा रहे है उन्हें घूम कर आना-जाना पड़ रहा है कलेक्टर को परेशानी बताई गई उन्होंने निराकरण का आश्वासन दिया है इस दौरान दापोरा निवासी किसान गणेश पाटिल, दशरथ महाजन, रघुनाथ पाटिल, भगवान हीरामन मौजूद थे

पिता के नाम का बिल हुआ माफ अब बकाया बताकर निजी ट्रांसफॉर्म उतार कर ले गए विद्युत विभाग के जिम्मेदार

जब विरोध किया तो उल्टा किसान के ऊपरी हावी हो गया विद्युत विभाग का हमला

शाजापुर सलसलाई सहित पूरे क्षेत्र में विद्युत विभाग के मनमाने दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है जहां वर्षों पूर्व के बिल किसानों को बकाया अचानक बढ़कर किसी की गाड़ी उठा रहे तो किसी का ट्रैक्टर तो कहीं निजी लगाए ट्रांसफर फॉर्म भी उतार कर ले जा रहे जब किसान उन्हें बताते हैं तो कहते हैं कि तुम्हारे पिताजी का बकाया है तुम्हारे उसे खेत का बकाया है गुमराह कर किसानों से लूट सके तो लूट की तर्ज पर अवैध वसूली के साथ परेशान का दौर चल रहा है आखिर विद्युत विभाग ऐसा क्यों कर रहा सलसलाई निवासी किसान कमल भिलाल पिता स्वर्गीय नारायण भिलाला जो की आदिवासी समाज से है ने बताया कि मेरे पिताजी की मृत्यु हुई लगभग 3 वर्ष हो गए वहीं पुराने खेत पर उनके नाम से कनेक्शन था वहां अभी तक वर्षों बीत गए हमें बिल नहीं मिला पूर्व में उक्त कनेक्शन को हमने खत्म कर माफी में हो गया था जहां अब अचानक एक लाख से ऊपर बकाया राशि बात कर पश्चिम विद्युत वितरण केंद्र सलसलाई के जिम्मेदार परेशान कर रहे और वही अब उक्त बिल की राशि बकाया मेरे पिताजी के नाम से आज बताइ जहां मैं नीचे ट्रांसफॉर्म लगाया उक्त ट्रांसफर फॉर्म पर कोई बकाया राशि नहीं है और बकाया राशि बताकर अभद्र व्यवहार कर उक्त ट्रांसफर को उतार कर ले गए जबकि मेरे पिताजी का माफी में नाम है वह अन्य कागज को लेकर उन्हें बताया कि हम लेकर आते पर बात सुनने को तैयार नहीं और अभद्र व्यवहार कर हमसे उक्त ट्रांसफर फॉर्म को उतार ले गए पूर्व में भी नगर का कई किसानों के बिल माफ होने के बाद भी पुराने बिल बात कर की गई थी जब्ती इसके पूर्व विद्युत विभाग के द्वारा किसान गोपाल सिंह जसवंत सिंह सहित अन्य किसानों से बिल जबकि उनके जमा होने बाद भी उनके वाहनों को जप्त कर ले गए थे जहां उनसे कोई बातचीत भी नहीं की और सीधा वहां उठाकर ले जा रहे जबकि बाद में कंप्लीट बल होने के बाद वह डॉक्यूमेंट बताने के बाद उक्त वाहन दे रहे जब इस बारे में किसान उनसे बात करते हैं तो किसानों को पुराने बिल बकाया होने सहित तुम्हारे पिताजी के नाम से बकाया होने अन्य तरह कैसे गुमराह कर रहे मामले में कनिष्ठी यंत्री मनोज मालवीय को फोन लगाया तो उन्होंने उठाया नहीं

अशासकीय विद्यालयों की मान्यता की आवेदन तिथि बढ़ी

राज्य शिक्षा केन्द्र ने कलेक्टर्स को जारी किया पत्र

बड़वानी से रघुनाथ सेन प्रदेश के अशासकीय विद्यालय की मान्यता नवीनीकरण और नवीन मान्यता की अंतिम तिथि अब बढ़ाकर 25 फरवरी 2025 निर्धारित की गई है। राज्य शिक्षा केन्द्र ने स्पष्ट किया है कि 25 फरवरी के बाद अंतिम तिथि में किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं की जा सकेगी। मान्यता संबंधी निर्देश पूर्व की तरह यथावत रहेंगे। प्रदेश में शिक्षण सत्र 2025-26 के लिये अशासकीय विद्यालयों की मान्यता नवीनीकरण और नवीन मान्यता आवेदन की अंतिम तिथि 7 फरवरी 2025 निर्धारित की गई थी। विलंब शुल्क के साथ अंतिम तिथि 14 फरवरी 2025 निर्धारित की गई थी।

अशासकीय विद्यालयों की दिक्कतों को देखते हुए राज्य शिक्षा केन्द्र ने आवेदन तिथि में वृद्धि की है। राज्य शिक्षा केन्द्र ने कलेक्टर्स और जिला परियोजना समन्वयक को इस संबंध में निर्देश जारी किये हैं। समेकित छात्रवृत्ति योजना स्कूल शिक्षा विभाग ने समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन के अंतर्गत समेकित छात्रवृत्ति योजना लागू की है। योजना का नोडल अधिकारी स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा निर्धारित किया गया है। समेकित छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत शासकीय और अशासकीय विद्यालयों में कक्षा 1ली से 12वी तक अध्ययनरत विद्यार्थियों को 6 विभागों की लगभग 20 प्रकार की छात्रवृत्ति शिक्षा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन स्वीकृत कर सीधे विद्यार्थी के खाते में भुगतान किये जाने की व्यवस्था की गई है।

योजना में प्रत्येक विद्यार्थी का नाम समग्र यूनिक आईडी के आधार पर उसके स्कूल के डाइस कोड के साथ मेपिंग कर कक्षावार, स्कूलवार नामांकन ऑनलाइन किये जाने का सिस्टम शिक्षा पोर्टल एनआईसी के माध्यम से तैयार कराया गया है। प्रत्येक छात्र की प्रोफाइल में संबंधित की जाति, माता-पिता का व्यवसाय, परिवार की वार्षिक आय, बीपीएल स्टेटस, छात्रावासी स्टेटस, पिछले वर्ष का परीक्षा परिणाम, जो छात्रवृत्ति गणना करने में आवश्यक होते हैं

कलेक्टर ने किया आबापुरी विद्यालय एवं छात्रावास का निरीक्षण

कलेक्टर सुश्री भव्या मित्तल ने 20 फरवरी को जिले के आदिवासी बहुल विकासखण्ड झिरन्या के आबापुरी में संचालित कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय एवं छात्रावास का निरीक्षण कर वहां की व्यस्थाओं को देखा। इस दौरान जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री आकाश सिंह भी मौजूद थे। छात्रावास के निरीक्षण के दौरान कलेक्टर सुश्री मित्तल ने बालिकाओं से छात्रावास में मिल रही सुविधाओं और भोजन के बारे में जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने छात्रावास अधीक्षिका को निर्देशित किया कि छात्रावास में साफ-सफाई एवं स्वच्छता की व्यवस्था दुरूस्त बनाएं रखें। बालिका छात्रावास में बालिकाओं की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दें। छात्रावास में अनुशासन बनाएं रखें और बालिकाओं को निर्धारित मैन्यू के अनुसार नाश्ता एवं भोजन प्रदान करें। इसमें किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होना चाहिए। कलेक्टर सुश्री मित्तल ने छात्रावास की बालिकाओं से चर्चा के दौरान कहा कि वे खूब मन लगाकर पढ़ाई करें और आगे की पढ़ाई कर अच्छे बड़े पदों पर जाने का प्रयास करें।

प्रवेश वर्मा को कैबिनेट मंत्री भाजपा कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न

धार- दिल्ली में भाजपा सरकार में धार विधायक श्रीमती नीना वर्मा के दामाद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा को कैबिनेट मंत्री बनाए जाने पर धार नगर के धानमंडी चौराहा पर आतिशबाजी कर मिठाई वितरित खुशियां मनाई इस मौके पर भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉ शरद विजय वर्गीय, पुर्व नगर अध्यक्ष अनिल जैन बाबा,मण्डल अध्यक्षद्वय जय राज देवड़ा व युवा मोर्चा पूर्व मंडल अध्यक्ष देवेंद्र रावल, कालीचरण सोनवानिया, प्रवीण गर्ग, प्रधान, अंकित भावसार, रॉकी आहूजा, सन्नी होड़ा, अतुल फकीरा , राजेश सोनी, पप्पू अरोरा जी, चेतन पंडाग्रे, कपिल श्रीवास्तव, अंकित जैन, निलेश मंडलोई सहित भाजपा नगर पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे।

अवैध शराब परिवहन के विरुद्ध राणापुर पुलिस की 20 दिन में दूसरी कार्यवाही माल ओर मुल्जिम पकड़ में आया

रानापुर- पुलिस अधीक्षक जिला झाबुआ पद्मविलोचन शुक्ल के द्वारा सभी थाना प्रभारीयो को अवैध गतिविधीयो में लिप्त अपराधियो की धरपकड करने हेतु निर्देशित किया गया था, जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रेमलाल कुर्वे एवं अनुविभागीय अधिकारी झाबुआ श्रीमति रुपरेखा यादव के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी राणापुर निरीक्षक दिनेश रावत द्वारा थाना राणापुर एवं चौकी कंजावानी की पुलिस टीम बना कर अवैध गतिविधीयो में लिप्त अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही की गई। मुखबीर की सुचना मिली की थाना राणापुर क्षेत्र के वगई रोड गिट्टी खदान के पास ग्राम मदनकुई में एक तुफान जीप जिसका वाहन क्रमांक त्छ्-03-क्क्-9328 में अग्रेजी शराब बीयर की पेटीयां भर कर ले जाई जा रही है, सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए पुलिस द्वारा घेरबंदी कर धरपकड की गई। उक्त तुफान वाहन में माउंट बीयर 6000 कम्पनी की कुल 76 पेटीया जो करीब 912 बल्क लीटर कीमती 2,37,120 रुपये एवं एक तुफान वाहन क्रमांक त्छ्-03-क्क्-9328 कीमती 10,00,000 रुपये कुल 12,37,120 रुपये का मश्रुका आरोपी दिलीप पिता सवला अजनार उम्र 22 साल निवासी कोरियापान थाना चन्द्रशेखर आजाद नगर जिला अलिराजपुर के कब्जे से विधीवत् जप्त कर थाना राणापुर पर अपराध क्रमांक 53/2025 धारा 34(2), 36 आबकारी एक्ट का पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया। उक्त सराहनीय कार्यवाही मे थाना राणापुर प्रभारी निरीक्षक दिनेश रावत, उपनिरीक्षक हीरालाल मालीवाड चौकी प्रभारी कंजावानी, सहायक उप निरीक्षक भेरुसिहं भुरिया, प्रधान आरक्षक 335 राजेन्द्र गणावा, आरक्षक 607 दिनेश, आरक्षक 691 सोहन, आरक्षक 671 शिवा, आरक्षक 196 अजमेर एवं आरक्षक 379 विजय का महत्वपुर्ण योगदान रहा ।

नगर परिषद ने सफाई कर्मचारियों को बांटी पीपीई किट

बदनावर। नगर परिषद ने सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए गुरुवार को पीपीई किट वितरित किए। साथ ही उन्हे स्वच्छता सर्वेक्षण के बारे में बताकर शहर को स्वच्छ व सुंदर बनाने की दिशा में काम करने का आव्हान किया। नगर परिषद अध्यक्ष मीना शेखर यादव, मुख्य नगर पालिका अधिकारी लालसिंह राठौर, नगर परिषद के स्वच्छता ब्रांड एंबेसेडर सामाजिक कार्यकर्ता सुजीत धोड़पकर के आतिथ्य मे निकाय के 50 सफाईकर्मियों को पीपीई किट में मास्क, दस्ताने, फेस शील्ड और सुरक्षात्मक कपड़े वितरित किए गए। वही शहर में स्थित नाली व नालों की सफाई के लिए कवर्ड बड़े जूते भी उपलब्ध कराए। ये किट कर्मचारियों को खतरनाक वायरस, बैक्टीरिया और अन्य संक्रामक तत्वों से बचाएगी। नपाध्यक्ष यादव ने संबोधित करते हुए कहा कि शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने में सफाईकर्मियों की भूमिका अहम है। सफाईकर्मी निकाय के नींव के पत्थर होते हैं। हमे स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर काम करना है। हमारा लक्ष्य है कि नगर परिषद पूरे प्रदेश में पहले नंबर पर आए। सीएमओ लालसिंह राठौर ने कहा कि सुरक्षा उपकरणों की उपलब्धता से कर्मचारियों में आत्मविश्वास बढ़ेगा और वे बिना किसी डर के अपना काम कर सकेंगे। ये किट न केवल उन्हें तत्काल खतरों से बचाएगी, बल्कि खतरनाक रसायनों और कीटनाशकों के संपर्क में आने से होने वाली दीर्घकालिक स्वास्थ्य समस्याओं से भी सुरक्षा प्रदान करेगी। सफाई कर्मचारी अक्सर अस्पतालों, सार्वजनिक शौचालयों जैसे उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में काम करते हैं, जहां संक्रमण का खतरा ज्यादा होता है। ब्रांड एंबेसेडर धोड़पकर ने भी सफ़ाईकर्मियों को संबोधित किया। इस मौके पर पार्षद व स्वच्छता विभाग के सभापति सुखराम देवदा, जगदीश पाटीदार, संतोष चौहान, दरोगा धर्मेंद्र समेत निकाय के सफाईकर्मी मौजूद थे।

बीजापुर पंचायत चुनावः गंगालुर जिला पंचायत सीट पर टेबुलेशन के बाद नाटकीय रूप से बदला नतीजा

हनमंत बोरे . सिटी चीफ (छग)

बीजापुर, बीजापुर जिले की गंगालुर जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 6 की सीट का चुनावी परिणाम नाटकीय मोड़ ले चुका है। पहले निर्दलीय प्रत्याशी राजू कलमु ने अपनी जीत का दावा कर जश्न मना लिया था, लेकिन टेबुलेशन के बाद सतेश एंड्रिक को 60 वोटों के अंतर से विजेता घोषित किया गया। इस घटनाक्रम ने जिले में चुनावी प्रक्रिया को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं।

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान 17 फरवरी को हुआ था। मतदान के बाद प्रारंभिक मतगणना में निर्दलीय प्रत्याशी राजू कलमु ने खुद को विजयी घोषित कर पूर्व मंत्री महेश गागड़ा के साथ रंग-गुलाल खेलते हुए जीत का जश्न मना लिया।

इसी सीट से निर्दलीय प्रत्याशी सतेश एंड्रिक ने भी अपनी जीत का दावा किया और अपने समर्थकों के साथ खुशी मनाई। यह स्थिति मतगणना में गड़बड़ी की ओर इशारा कर रही थी, जिससे दोनों ही प्रत्याशियों और उनके समर्थकों ने मतगणना प्रक्रिया पर आपत्ति दर्ज कराई।

इस विवाद के बाद, चुनाव आयोग ने टेबुलेशन प्रक्रिया शुरू की, जिसमें सभी वोटों की पुनर्गणना और सत्यापन किया गया। टेबुलेशन के बाद नतीजा बदल गया और सतेश एंड्रिक को आधिकारिक रूप से 60 वोटों से विजेता घोषित कर दिया गया।

चुनावों में टेबुलेशन प्रक्रिया तब लागू की जाती है जब मतगणना में त्रुटि, विवाद या अनियमितता की संभावना होती है।

इसमें सभी मतदान केंद्रों के आंकड़ों को दोबारा सत्यापित किया जाता है और मतों की गिनती की सटीकता सुनिश्चित की जाती है।

गंगालुर पंचायत चुनाव का यह मामला बताता है कि चुनाव में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए मजबूत व्यवस्थाओं की आवश्यकता है। टेबुलेशन प्रक्रिया ने सही परिणाम प्रस्तुत किया, लेकिन यह दर्शाता है कि प्रारंभिक मतगणना में सावधानी बरतनी चाहिए।

चुनाव आयोग को भविष्य में ऐसे विवादों से बचने के लिए मतदान और मतगणना प्रक्रियाओं में सुधार लाना चाहिए ताकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया की विश्वसनीयता बनी रहे।

आदि महोत्सव में बस्तर के महुआ दारू और चापड़ा चटनी का दिल्लीवासियों पर जादू

राजीव खरे . सिटी चीफ (छग)

नई दिल्ली, नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में आयोजित आदि महोत्सव 2025 में बस्तर के पारंपरिक व्यंजनों ने दिल्लीवासियों का दिल जीत लिया है। बीजापुर जिले के मुरकीनार गांव के निवासी राजेश यालम ने महोत्सव में बस्तरिया फूड का एकमात्र स्टॉल स्थापित किया है, जहां महुआ दारू और चापड़ा चटनी (चींटियों की चटनी) विशेष आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं।

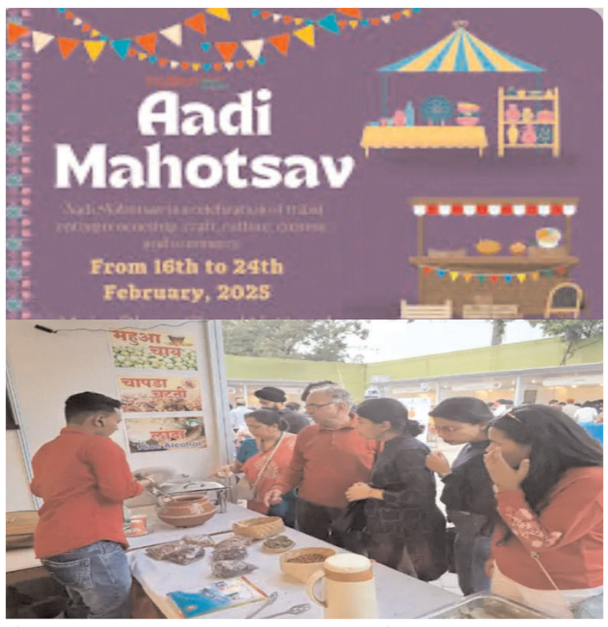

राजेश यालम, जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र से आते हैं, ने अपने स्टॉल पर बस्तर के 27 विभिन्न पारंपरिक व्यंजनों की प्रस्तुति की है। हालांकि, महुआ दारू और चापड़ा चटनी ने विशेष लोकप्रियता हासिल की है। महोत्सव के शुरुआती दो दिनों में ही दिल्लीवासियों ने 50 लीटर महुआ दारू और 25 किलोग्राम चापड़ा चटनी का आनंद लिया। इन व्यंजनों का अनोखा स्वाद और पारंपरिक महत्व लोगों को आकर्षित कर रहा है।

आदि महोत्सव 2025, जो 16 से 24 फरवरी तक आयोजित हो रहा है, का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। इस महोत्सव का उद्देश्य देशभर के आदिवासी समुदायों की कला, संस्कृति, शिल्प और व्यंजनों को प्रदर्शित करना है। राजेश यालम का स्टॉल विशेष रूप से बस्तर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को उजागर कर रहा है।

राजेश बताते हैं कि महुआ दारू बस्तर के आदिवासी समुदायों का पारंपरिक पेय है, जिसे महुआ फूलों से तैयार किया जाता है। वहीं, चापड़ा चटनी लाल चींटियों और उनके अंडों से बनाई जाती है, जो अपने तीखे स्वाद और स्वास्थ्यवर्धक गुणों के लिए प्रसिद्ध है। दिल्ली के लोग इन व्यंजनों के अनोखे स्वाद का आनंद ले रहे हैं और बस्तर की सांस्कृतिक धरोहर से रूबरू हो रहे हैं।

महोत्सव में शामिल एक दिल्ली निवासी ने बताया, मैंने पहली बार महुआ दारू और चापड़ा चटनी का स्वाद चखा। यह वास्तव में लाजवाब है। बस्तर की संस्कृति और व्यंजनों के बारे में जानकर बहुत अच्छा लगा।

आदि महोत्सव 2025 में देशभर के विभिन्न आदिवासी समुदायों के शिल्प, कला, संगीत और व्यंजनों का संगम देखने को मिल रहा है। इस महोत्सव के माध्यम से आदिवासी संस्कृति की विविधता और समृद्धि को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित करने का प्रयास किया जा रहा है।

राजेश यालम जैसे उद्यमियों के प्रयासों से न केवल बस्तर की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा मिल रहा है, बल्कि स्थानीय समुदायों को आर्थिक सशक्तिकरण का अवसर भी प्राप्त हो रहा है। आदि महोत्सव जैसे आयोजन आदिवासी समुदायों की पहचान और संस्कृति को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

यदि आप भी बस्तर के पारंपरिक व्यंजनों का स्वाद चखना चाहते हैं और आदिवासी संस्कृति के विविध रंगों से रूबरू होना चाहते हैं, तो 24 फरवरी तक चलने वाले इस महोत्सव में अवश्य शामिल हों।

सतना के प्रतीक सिंह करेंगे भारत का प्रतिनिधित्व

कूडो वर्ल्ड कप 2025 के लिए हुआ चयन

उमेश कुशवाहा . सिटी चीफ

सतना, जिले के लिए गर्व का क्षण अंतरराष्ट्रीय कूडो चैंपियन प्रतीक सिंह का कूडो वर्ल्ड कप 2025 के लिए हुआ चयन, जो बुल्गारिया, यूरोप में आयोजित होने जा रहा है, यह टूर्नामेंट दुनिया का सबसे बड़ा और प्रतिष्ठित कूडो चैम्पियनशिप होगा, जिसमें विभिन्न देशों के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। कूडो वर्ल्ड कप 2025 के लिए 8-9 फरवरी को सूरत इंडोर स्टेडियम में ट्रायल्स आयोजित किए गए थे, जिनमें केवल नवंबर 2024 में आयोजित राष्ट्रीय चैंपियनशिप के पदक विजेता ही भाग ले सकते थे। प्रतीक ने इन कठिन मुकाबलों में शानदार प्रदर्शन कर भारतीय टीम में अपनी जगह सुनिश्चित कर ली। वर्तमान में प्रतीक आयकर विभाग, मुंबई में कार्यरत हैं और इससे पहले भी भारत का कई बार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, जहां उन्होंने अपनी शानदार प्रतिभा और कौशल से देश का नाम रोशन किया है। उनकी इस असाधारण उपलब्धि से सतना जिले का गौरव और भी बढ़ गया है। यह न केवल शहर बल्कि पूरे देश के लिए सम्मान की बात है कि एक और भारतीय एथलीट वैश्विक मंच पर अपनी चमक बिखेरने को तैयार है। दिवंगत शिहान R P ने उन्हें एक बेहतरीन खिलाड़ी और एक अच्छा इंसान बनने के लिए तैयार किया। इसके अलावा, सतना कूडो एसोसिएशन के सचिव सेंपई यश गुप्ता,अध्यक्ष- अशोक सिंह,कोषाध्यक्ष- सेंसेई लखन गुप्ता और की ऑफ़ लाइफ अकैडमी के डायरेक्टर सेंसाई भरत गुप्ता एवं अकैडमी के खिलाड़ियो ने शुभकामनाएँ दी और उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

शासकीय महाविद्यालय लालबर्रा के राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर के द्वितीय दिवस कार्यक्रम का आयोजन।

लकेश पंचेश्वर । सिटी चीफ

लालबर्रा, म.प्र. शासन उच्च षिक्षा विभाग के निर्देषानुसार शासकीय महाविद्यालय लालबर्रा के राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर के द्वितीय दिवस का शुभारंभ मॉ सरस्वती एवं स्वामी विवेकानंद के छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्जवलन,पूजन अर्चन व माल्यार्पण कर किया गया। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. सुरेन्द्र कुमार खण्डायत के निर्देशन में राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर के द्वितीय दिवस का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर के द्वितीय दिवस की थीम ''सायबर अपराध एवं मल्टीमिडिया'' है। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री सुनील चतुर्वेदी थाना प्रभारी लालबर्रा ने अपने व्याख्यान में ए.टी.एम कार्ड व ओ.टी.पी से संबंधित धोखाधडी के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की तथा ऑनलाईन पेमेंट और ऑनलाईन शॉपिंग में सूझबूझ से

काम लेने की सलाह दी। सावित्री बाई फूले दल से अंजली बाहेश्वर ने गीत एवं स्वाति दमाहे ने भाषण की प्रस्तुति दी। रानी लक्ष्मीबाई दल से आदित्य मर्सकोले,लुखमनी यादव ने भाषण एवं सोनम पन्द्रे ने गीत की प्रस्तुति दी।महाराणा प्रताप दल से दीक्षा कटरे के द्वारा गीत और पलक सूर्यवंशी ने भाषण की प्रस्तुति दी। छत्रपति शिवाजी दल से अंजली कल्याणी के द्वारा भाषण एवं मितेश शिववंषी द्वारा गीत की प्रस्तुति दी गई। शिविर प्रभारी डॉ. विवेक खरगाल के द्वारा देशभक्ति गीत का गायन किया गया। ग्राम पंचायत बेलगांव के सरपंच डॉ. अरविन्द पंचेश्वर ने अपने व्याख्यान में विद्यार्थियों को स्वावलंबी बनने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम प्रभारी डॉ. प्रदीप कुमार भिमटे द्वारा कार्यक्रम का आभार प्रदर्शन किया गया। राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर के द्वितीय दिवस में श्रीमती माधुरी पुसे,श्रीमतीआशा कारे,लकेश गेडाम,रामदयाल मथारे एवं विद्यार्थियों का सराहनीय योगदान रहा।

बुजुर्ग महिला की डंडे से पीट-पीटकर हत्या

पुलिस ने हत्यारोपी को किया गिरफ्तार

गौरव सिंघल 7 सिटी चीफ (उप्र)

सहारनपुर। सहारनपुर जनपद के थाना कुतुबशेर क्षेत्र में एक बुजुर्ग महिला की डंडे से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। हत्याकांड को अंजाम देने वाला आरोपी महिला का रिश्ते का पोता है। जानकारी के अनुसार स्मैक के लिए रुपये नहीं देने पर बुजुर्ग महिला की डंडे से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद आरोपी नकदी व जेवरात लूटकर ले गया। पुलिस ने हत्यारोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अंबाला रोड पर खुर्जा मिल स्थित वाल्मीकि बस्ती में 75 वर्षीय सोमी घर में अकेली रहती थी। उसके पति कालीचरण की मौत हो चुकी है, जबकि बेटा अलग रहता है। पड़ोस में रहने वाला अंकुश रिश्ते में सोमी का पोता लगता है। देर रात अंकुश दादी के मकान में घुस गया। उसने स्मैक खरीदने के लिए रुपये मांगे, लेकिन सोमी ने रुपये देने से मना कर दिया। इसके बाद अंकुश ने गुस्से में आकर हाथ में लिए डंडे से सिर पर कई वार किए, जिससे सोमी की मौके पर ही मौत हो गई। हत्या करने के बाद आरोपी कमरे में दो बक्सों से 46,537 रुपये, सोने-चांदी के दो-दो कड़े सहित अन्य जेवरात लेकर भाग गया। बाद में आसपास के लोगों को पता चला। पुलिस ने देर रात हत्या का मामला दर्ज किया। छानबीन के बाद आरोपी अंकुश को दबनी कब्रिस्तान के पास से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से लूटे गए जेवरात और नकदी बरामद हो गई है।

बुजुर्ग महिला की डंडे से पीट-पीटकर हत्या

गौरव सिंघल 7 सिटी चीफ (उप्र)

सहारनपुर। सहारनपुर जनपद के थाना कुतुबशेर क्षेत्र में एक बुजुर्ग महिला की डंडे से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। हत्याकांड को अंजाम देने वाला आरोपी महिला का रिश्ते का पोता है। जानकारी के अनुसार स्मैक के लिए रुपये नहीं देने पर बुजुर्ग महिला की डंडे से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद आरोपी नकदी व जेवरात लूटकर ले गया। पुलिस ने हत्यारोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अंबाला रोड पर खुर्जा मिल स्थित वाल्मीकि बस्ती में 75 वर्षीय सोमी घर में अकेली रहती थी। उसके पति कालीचरण की मौत हो चुकी है, जबकि बेटा अलग रहता है। पड़ोस में रहने वाला अंकुश रिश्ते में सोमी का पोता लगता है। देर रात अंकुश दादी के मकान में घुस गया। उसने स्मैक खरीदने के लिए रुपये मांगे, लेकिन सोमी ने रुपये देने से मना कर दिया। इसके बाद अंकुश ने गुस्से में आकर हाथ में लिए डंडे से सिर पर कई वार किए, जिससे सोमी की मौके पर ही मौत हो गई। हत्या करने के बाद आरोपी कमरे में दो बक्सों से 46,537 रुपये, सोने-चांदी के दो-दो कड़े सहित अन्य जेवरात लेकर भाग गया। बाद में आसपास के लोगों को पता चला। पुलिस ने देर रात हत्या का मामला दर्ज किया। छानबीन के बाद आरोपी अंकुश को दबनी कब्रिस्तान के पास से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से लूटे गए जेवरात और नकदी बरामद हो गई है।

डोंगरगढ़ में फर्जी सिम रैकेट का भंडाफोड़

अंतरराष्ट्रीय साइबर क्राइम से जुड़े तार, पुलिस ने दबोचा मास्टरमाइंड

राजीव खरे . सिटी चीफ (छग)

डोंगरगढ़, छत्तीसगढ़ पुलिस की साइबर सेल ने डोंगरगढ़ में एक बड़े साइबर क्राइम रैकेट का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने रेलवे चौक स्थित 'अज्जू मोबाइल' नामक दुकान के संचालक अजय मोटघरे को गिरफ्तार किया है, जो फर्जी सिम कार्डों की अवैध बिक्री कर रहा था। जांच में खुलासा हुआ है कि इन सिम कार्डों का इस्तेमाल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऑनलाइन ठगी, बैंक धोखाधड़ी और साइबर अपराधों के लिए किया जा रहा था।

साइबर पुलिस की छापेमारी में बड़ी मात्रा में फर्जी सिम कार्ड, कई मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए गए हैं। प्रारंभिक जांच में पता चला कि अजय मोटघरे द्वारा जारी किए गए सिम कार्ड संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), श्रीलंका, नेपाल और म्यांमार जैसे देशों में साइबर अपराधियों के हाथों बेचे गए थे।

यह मामला तब सामने आया जब साइबर अपराध से जुड़ी कई शिकायतों की जांच के दौरान पुलिस को एक अंतरराष्ट्रीय साइबर क्राइम नेटवर्क के सुराग मिले। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, यह नेटवर्क न केवल फर्जी बैंक खातों को सक्रिय करने के लिए इन सिम कार्डों का उपयोग कर रहा था, बल्कि ऑनलाइन ठगी और साइबर जासूसी जैसी गतिविधियों में भी संलिप्त था।

इस मामले को लेकर साइबर पुलिस ने 'ऑपरेशन साइबर शील्ड' के तहत कार्रवाई की, जिसमें म्यूल बैंक अकाउंट (धोखाधड़ी के लिए खोले गए बैंक खाते) बनाने के लिए फर्जी सिम कार्ड बेचने वाले 13 पीओएस एजेंटों को भी गिरफ्तार किया गया है। इस ऑपरेशन के तहत अब तक कुल 98 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है।

इस मामले ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि साइबर अपराध सिर्फ स्थानीय स्तर पर सीमित नहीं हैं, बल्कि इसके तार अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध गिरोहों से जुड़े हो सकते हैं। फर्जी सिम कार्ड का इस्तेमाल कई तरह की अवैध गतिविधियों के लिए किया जाता है, जिनमें शामिल हैं-

- बैंक धोखाधड़ी और ऑनलाइन ठगी
- राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर साइबर जासूसी
- फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट्स से अफवाह फैलाना और लोगों को ठगना
- डार्क वेब के जरिए डेटा की अवैध बिक्री

इस मामले को देखते हुए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों ने नागरिकों से सावधानी बरतने की अपील की है। साइबर अपराध से बचने के लिए निम्नलिखित उपाय जरूरी हैं-

- अपने मोबाइल नंबर और व्यक्तिगत जानकारी को सुरक्षित रखें और किसी अज्ञात व्यक्ति को न दें।
- किसी भी संदिग्ध लिंक, ईमेल या एसएमएस पर क्लिक करने से बचें।
- दो-कारक प्रमाणीकरण का उपयोग करें ताकि अकाउंट्स अधिक सुरक्षित रहें।
- सार्वजनिक वाई-फाई नेटवर्क का इस्तेमाल करते समय सतर्क रहें।
- अगर किसी अनजान व्यक्ति का फोन आए और बैंक या ओटीपी की जानकारी मांगे, तो फौरन पुलिस को सूचित करें।

साइबर सेल अब इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटी है और अजय मोटघरे के अन्य संपर्कों की जांच कर रही है। पुलिस का मानना है कि इस नेटवर्क में और भी कई लोग शामिल हो सकते हैं, जो फर्जी सिम कार्डों को बेचने और उनका इस्तेमाल करने में लिप्त हैं।

साइबर पुलिस ने जनता से अपील की है कि अगर किसी को साइबर अपराध से जुड़ी कोई संदिग्ध गतिविधि दिखे, तो तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन या साइबर हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत दर्ज कराएं। इस मामले की विस्तृत जांच जारी है और जल्द ही और गिरफ्तारियां हो सकती हैं।

ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने के बाद भारत के खिलाफ लिए 5 बड़े फैसले

इंटरनेशनल डेस्क: अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले महीने में भारत के खिलाफ कई अहम फैसले लिए हैं, जो देश की राजनीति, व्यापार और अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर गहरा असर डाल सकते हैं। इन फैसलों ने भारत को कई मोर्चों पर कमजोर किया है, और उनका असर आने वाले समय में महसूस किया जाएगा। आइए जानते हैं वो 5 बड़े झटके जो ट्रंप ने भारत को दिए-

1. एलन मस्क की टेस्ला को भारत में लाने से रोकना

टेस्ला, जो भारत में अपनी इलेक्ट्रिक कारों के निर्माण की योजना बना रही थी, को ट्रंप ने बड़ा झटका दिया है। ट्रंप का मानना है कि अगर मस्क भारत में कार निर्माण की फैक्ट्री लगाते हैं तो यह अमेरिका के लिए अनुचित होगा। इससे अमेरिकी नौकरियां और निवेश विदेश जा सकते हैं। इस फैसले ने टेस्ला के भारत में विस्तार के प्रयासों को रोक दिया है, जो भारतीय बाजार के लिए एक बड़ा झटका है।

2. भारतीय उत्पादों पर भारी टैरिफ लगाना

ट्रंप प्रशासन ने भारतीय उत्पादों पर 100त्न टैरिफ लगाने की धमकी दी है, जिससे भारतीय निर्यातकों पर दबाव बढ़ेगा। इससे भारतीय व्यापार और उद्योगों पर नकारात्मक असर पड़ सकता है, खासकर उन उद्योगों पर जो अमेरिका से निर्यात करते हैं। इस कदम से व्यापारिक रिश्तों में तनाव पैदा हो सकता है।

3. अमेरिकी सहायता में कटौती

ट्रंप प्रशासन ने विदेशी सहायता में कटौती करने का फैसला लिया है, जिससे भारत को मिलने वाली अमेरिकी मदद पर असर पड़ेगा। इससे भारत के स्वास्थ्य, कृषि, और शिक्षा क्षेत्रों में चल रही योजनाओं को खतरा हो सकता है, और कई परियोजनाओं को रोकने या धीमा करने का जोखिम पैदा हो गया है।

4. भारतीय नागरिकों की अपमानजनक वापसी

ट्रंप प्रशासन ने 200 से ज्यादा भारतीय नागरिकों को अवैध प्रवासियों के रूप में भारत भेजने का आदेश दिया। इन नागरिकों को सैन्य विमान में हाथ-पैर में हथकड़ियां लगाकर भेजा गया, जिससे भारत में एक अपमानजनक स्थिति उत्पन्न हो गई। इस तरह के व्यवहार से भारतीयों के खिलाफ अमेरिका की नीतियों पर सवाल उठे हैं।

5. तेजस के इंजनों की आपूर्ति में देरी

भारत ने अमेरिकी कंपनी GE से अपने तेजस फाइटर जेट के लिए इंजन की डील की थी, लेकिन अमेरिकी कंपनी GE ने आपूर्ति में लगातार देरी की। इस देरी से भारत की रक्षा योजनाओं को गंभीर नुकसान हुआ है और भारत को रूस से इंजन लेने पर विचार करना पड़ा है। ट्रंप के फैसलों ने अमेरिका-भारत रक्षा सहयोग पर भी असर डाला है।

ट्रंप के पहले कार्यकाल में भी भारत को ऐसे ही झटके दिए गए थे* जैसे कि भारत को GSP से बाहर करना और H-vB वीजा पर सख्ती लगाना। हालांकि, कई रक्षा उपकरणों की बिक्री हुई, फिर भी तकनीकी एक्सपोर्ट पर रोक बनी रही।

मिट्टी में मिला चीन का महंगा सपना

1 ट्रिलियन डॉलर कर्ज में डूबा हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट

इंटरनेशनल डेस्क: चीन के हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट पर भारी कर्ज चढ़ गया है, जिसका कारण कम सवारी, अनियंत्रित विस्तार और वित्तीय स्थिति की सुस्ती है। चीन राज्य रेलवे समूह ने स्वीकार किया है कि कर्ज-से-संपत्ति अनुपात 63.8 प्रतिशत तक पहुंच गया है, जो स्वस्थ अनुपात 50 प्रतिशत से कहीं अधिक है। चीन ने 70,000 किलोमीटर के उच्च गति रेल नेटवर्क के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अत्यधिक निवेश किए हैं, जिसके कारण अस्थिर कर्ज का बोझ बढ़ गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह उच्च गति रेल प्रोजेक्ट अब एक बड़े पैसे के गड्ढे में बदल चुका है क्योंकि ष्टस्त्रन्न का कर्ज लगभग 1 ट्रिलियन डॉलर के पास पहुंच चुका है। 2035 तक 70,000 किलोमीटर का नेटवर्क बनाने की योजना है।

यह बड़ा निवेश चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के आर्थिक मॉडल पर आधारित है, जो विकास को बुनियादी ढांचे पर खर्च करके बढ़ाना चाहता है। हालांकि, यह भारी कर्ज और वित्तीय जिम्मेदारियों के रूप में बहुत बड़ी कीमत चुका रहा है। बीजिंग जियाटोंग विश्वविद्यालय के विद्वान झाओ जियान ने 2019 में आलोचना की थी कि चीन ने उच्च गति रेल के वित्तीय खतरे को नजरअंदाज किया, खासकर उन क्षेत्रों में जहां यात्री कम थे। उनका कहना था, दुनिया के सबसे बड़े उच्च गति रेल नेटवर्क का होना, लेकिन यातायात घनत्व कम होना, बड़े वित्तीय जोखिम को दिखाता है। ऐसे नेटवर्क के निर्माण से चीन रेलवे कॉरपोरेशन और स्थानीय सरकारों पर अधिक कर्ज का बोझ पड़ सकता है, जो चीन की अर्थव्यवस्था के लिए एक 'ग्रे राइनो' (स्पष्ट खतरा) बन सकता है।

हांगकांग के व्यवसायी और लेखक डेसमंड शुम ने कहा कि बढ़ते कर्ज का कारण यह है कि स्थानीय सरकारों ने उम्मीद की थी कि उच्च गति रेल के निर्माण के बाद वे ज़मीन की बिक्री से भारी मुनाफा कमाएंगे, लेकिन रियल एस्टेट बबल के फूटने के बाद यह रणनीति सफल नहीं हो पाई।

अब स्थानीय सरकारों के पास कर्ज है, और उच्च गति रेल नेटवर्क को चलाना भी मुश्किल हो गया है, जो खुद को वित्तीय रूप से खड़ा नहीं कर पा रहा है। इन परियोजनाओं का फंड स्थानीय सरकारें भी देती हैं, लेकिन अब आर्थिक मंदी और रियल एस्टेट संकट के कारण इनकी आय में कमी आई है। यही कारण है कि कई उच्च गति रेल परियोजनाओं को रुकना पड़ा है, जो और भी वित्तीय समस्याएं पैदा कर रहा है। एक रेटिंग एजेंसी S&P ग्लोबल का कहना है कि अधूरी परियोजनाओं की समस्या भी बढ़ सकती है और वित्तीय दबाव को और बढ़ा सकती है। पहले जिसे चीन के आर्थिक विकास का प्रतीक माना जाता था, अब वही उच्च गति रेल परियोजनाएं भारी कर्ज संकट का कारण बन गई हैं। अमेरिकी अर्थशास्त्री डेवि हुआंग का कहना है कि इन रेल परियोजनाओं को बनाए रखने के लिए बड़ी रकम की आवश्यकता है, हालांकि वे कम उपयोग हो रही हैं, और इस कारण कर्ज समस्या और भी गंभीर हो गई है। विश्लेषकों का कहना है कि चीन सरकार का ध्यान नए रेल मार्गों पर केंद्रित है, जबकि देश की जनसंख्या आने वाले दशकों में लगभग 2 करोड़ घटने का अनुमान है। इस स्थिति में, इन उच्च गति रेल परियोजनाओं में निवेश अब जोखिमपूर्ण साबित हो रहा है, और यह चीन की अर्थव्यवस्था के लिए एक कठिन झटका हो सकता है।

मृत्यु को लेकर वैज्ञानिकों ने की नई खोज

मरने के बाद दूसरी दुनिया में चली जाती है आत्मा

नेशनल डेस्क. मृत्यु के बाद आत्मा कहां जाती है। इस बारे में कोई ठोस प्रमाण नहीं हैं, लेकिन कई धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताएं हैं। उदाहरण के लिए प्राचीन यूनानी मानते थे कि मरने के बाद चेरोन नामक एक नाविक आत्मा को दूसरी दुनिया में ले जाता है। वहीं अब ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने एक नई खोज की है, जिससे यह माना जा रहा है कि मृत्यु के बाद आत्मा का दूसरी दुनिया में जाना एक रासायनिक प्रक्रिया का हिस्सा हो सकता है।

क्या कहते हैं वैज्ञानिक?

ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि एक विशेष रसायन मृत्यु के समय हमारे दिमाग में सक्रिय हो जाता है, जिसे साइकेडेलिक न्यूरोकेमिकल कहा जाता है। यह रसायन शरीर से आत्मा को बाहर निकालकर दूसरी दुनिया में ले जाने का काम करता है।

लंदन के इंपीरियल कॉलेज के शोधकर्ताओं के अनुसार, निकट-मृत्यु अनुभवों के दौरान मतिभ्रम या विचित्र अनुभव होते हैं। उनमें डीएमटी (डायमेथाइलट्रिप्टामाइन) नामक रसायन का महत्वपूर्ण योगदान होता है। यह रसायन हमारे दिमाग में स्वाभाविक रूप से पाया जाता है। इस रसायन के कारण व्यक्ति को मृत्यु के बाद दिवंगत प्रियजनों की उपस्थिति, स्वर्ग जैसी जगहें, या भगवान की आवाज सुनाई दे सकती है।

चूहों पर किए गए शोध से मिली जानकारी

वैज्ञानिकों ने इस रसायन पर अब तक चूहों पर शोध किया है। चूहों में डीएमटी की उपस्थिति और इसके प्रभावों को समझने के बाद वैज्ञानिकों ने यह निष्कर्ष निकाला कि यह रसायन मृत्यु के समय हमारे दिमाग में तेजी से भर जाता है और इसी के चलते व्यक्ति को ऐसे अनुभव होते हैं, जो मृत्यु के बाद की दुनिया को दर्शाते हैं। हालांकि, यह खोज अभी शुरुआती चरण में है और इस पर और अधिक शोध की आवश्यकता है, लेकिन इसने मृत्यु और आत्मा के विषय पर एक नई दिशा में सोचने की संभावना को जन्म दिया है।

दिल्ली सरकार का बड़ा कदमः अफसरों को लौटाया उनके मूल विभागों में, आतिशी के निजी स्टाफ की सेवाएं समाप्त

नेशनल डेस्क. दिल्ली में नई सरकार के गठन के बाद, मुख्यमंत्री और मंत्रियों ने कई बड़े प्रशासनिक फैसले किए हैं। इनमें से एक महत्वपूर्ण कदम था दिल्ली सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों का फेरबदल। सरकार ने यह फैसला लिया कि सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को उनके मूल विभागों में रिपोर्ट करने के लिए कहा जाएगा। पूर्व सरकार द्वारा जिन अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति पर दूसरे स्थानों पर भेजा गया था, उन्हें तुरंत अपने मूल विभागों में वापस भेज दिया गया है।

इस निर्णय का उद्देश्य सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और कार्यक्षमता सुनिश्चित करना है। दिल्ली सरकार ने पिछले सप्ताह सभी विभागों से यह जानकारी मांगी थी कि पूर्व सरकार द्वारा नियुक्त किए गए कॉन्ट्रैक्ट और निजी स्टाफ का विवरण प्रदान किया जाए। इसके बाद सरकार ने फैसला लिया कि जिन अधिकारियों की नियुक्ति दूसरे विभागों में की गई थी, उन्हें तुरंत उनके मूल विभागों में वापस भेजा जाएगा। इसी प्रकार, पूर्व मुख्यमंत्री और उनके मंत्रियों के निजी स्टाफ की सेवाएं भी समाप्त कर दी गई हैं। यह फैसला नई सरकार ने अपने प्रशासनिक ढांचे को प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए लिया है।

पूर्व सरकार के कार्यकाल में कई अधिकारियों को बोर्ड और कॉर्पोरेशन जैसे दूसरे सरकारी विभागों में भेजा गया था, लेकिन नई सरकार ने सभी को उनके मूल विभागों में वापस भेजने का आदेश दिया है। इस कदम से अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में समन्वय और प्रभावशीलता बढ़ाने की उम्मीद है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि नई सरकार का यह फैसला अपने प्रशासनिक सुधारों का हिस्सा है, जिससे अधिकारियों के कामकाज में सुधार होगा और भ्रष्टाचार को रोकने में मदद मिलेगी।

चेक गणराज्य के शॉपिंग सेंटर में चाकू हमले से 2 लोगों की मौत, किशोर गिरफ्तार

इंटरनेशनल डेस्क: चेक गणराज्य के एक शॉपिंग सेंटर में बृहस्पतिवार को चाकू से किये गये हमले में दो महिलाओं की मौत हो गयी। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि प्राग के पूरब में करीब 100 किलोमीटर दूर ह्राडेक क्रालोव शहर के एक स्टोर में चाकू से किये गये हमले के सिलसिले में उसने एक किशोर संदिग्ध को हिरासत में लिया है। पहले कहा गया था कि दोनों महिलाएं घायल हो गयी थीं और उनमें से एक की स्थिति गंभीर है। बाद में पुलिस ने कहा कि दोनों महिलाओं की मौत हो गयी। उनकी पहचान नहीं हो पायी है। इस घटना के बाद घटनास्थल से करीब एक किलोमीटर की दूरी पर पुलिस ने 16 वर्षीय एक किशोर को हिरासत में लिया। समीप ही एक चाकू मिला। प्रधानमंत्री पेट्र फियाला ने इस हमले में जान गंवाने वाली महिलाओं के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने 'एक्स पर लिखा, ''आज ह्राडेक क्रालोव में जो कुछ हुआ है, वह बिल्कुल समझ से परे और भयानक कृत्य है। वैसे इस हमले का मकसद तत्काल पता नहीं चल पाया है। पुलिस का कहना है कि स्थिति नियंत्रण में है और लोगों को कोई खतरा नहीं है। इस संबंध अन्य कोई विवरण तत्काल उपलब्ध नहीं है।

करांची में सबसे ऊंची मीनार पर लहराया तिरंगा, पाकिस्तान की हेकड़ी रह गई धरी !

इंटरनेशनल डेस्क: पाकिस्तान की तमाम कोशिशों के बावजूद कराची के स्टेडियम में भारतीय तिरंगा शान से लहरा रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए स्टेडियम में सभी भाग लेने वाले देशों के झंडे लगाए गए थे, लेकिन भारत के तिरंगे को लगाने से इनकार किया गया था। हालांकि, BCCI के कड़े रुख के बाद PCB को झुकना पड़ा और अब पूरे पाकिस्तान के सामने उसकी फजीहत हो रही है। बुधवार को कराची स्टेडियम की सबसे ऊंची मीनार पर भारतीय तिरंगा लहराता नजर आया। यह वही पाकिस्तान था, जो दावा कर रहा था कि भारत का तिरंगा उसके स्टेडियम में नहीं लगाया जाएगा। लेकिन अब न सिर्फ पाकिस्तान का स्टेडियम है बल्कि वहां तिरंगा भी भारत का ही लहरा रहा है ।

इससे पहले PCB ने यह तर्क दिया था कि जब भारत की टीम पाकिस्तान नहीं आ रही है, तो उसका झंडा लगाने की जरूरत नहीं। लेकिन BCCI की सख्ती के आगे PCB की एक न चली । PCB ने इस मामले में ICC को बीच में खींचने की कोशिश की लेकिन सच्चाई यह है कि ICC में भी BCCI की पकड़ इतनी मजबूत है कि वह भारत के खिलाफ कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं कर सकता। खुद पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस और विशेषज्ञ मान रहे हैं कि पाकिस्तान की औकात BCCI के आगे कुछ भी नहीं । पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें कराची स्टेडियम में सभी टीमों के झंडे तो लगे थे, लेकिन भारत के तिरंगे को जानबूझकर हटाया गया था । जब यह बात BCCI तक पहुंची तो उन्होंने तुरंत ICC और PCB पर दबाव बनाया । नतीजा यह हुआ कि पाकिस्तान को झुकना पड़ा और पूरे देश के सामने फजीहत झेलनी पड़ी ।

पाकिस्तान के कुछ लोगों ने इस मुद्दे पर भारत के ऐतिहासिक स्थलों से तुलना करने की कोशिश की, लेकिन हकीकत यह है कि भारत की ताकत और वैश्विक स्थिति से पाकिस्तान कोसों दूर है । पाकिस्तान में सुरक्षा हालात इतने खराब हैं कि वहां कोई विदेशी नेता बिना कड़ी सुरक्षा के नहीं आ सकता जबकि भारत में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी परिवार समेत बेफिक्री से घूम चुके हैं । इस घटना ने एक बार फिर दिखा दिया कि जब बात भारत की प्रतिष्ठा की आती है, तो BCCI और भारत सरकार किसी के आगे झुकने वाले नहीं हैं । पाकिस्तान की बार-बार की जाने वाली राजनीति और दावे बेकार साबित हुए, और कराची स्टेडियम में तिरंगा लहराकर भारत ने अपनी ताकत दिखा दी ।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक श्रीमती ज्योती मिश्रा द्वारा कॉम्पेक प्रिंटर्स प्रा. लि. फ्री प्रेस हाउस 3/54, प्रेस कॉम्पलेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 45ए गुप्ता चैम्बर पहली मंजिल जावरा कंपाउंड इंदौर, (म.प्र.) से प्रकाशित।
प्रधान सम्पादक : अशीष मिश्रा आर.एन.आई. पंजीयन क्रमांक : एमपी/एच/आइएन 2009/34385 फोन नं : 0731-4202569 फैक्स नं : 0731-4202569